

प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 1,22,100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन

हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा मिशन को जन आंदोलन में बदल रही है: पीएम

नई दिल्ली, एजेंसी
हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा मिशन को जन आंदोलन में बदल रही है: प्रधानमंत्री

हम समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सेवा भावना से कार्य कर रहे हैं: प्रधानमंत्री

यह सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है कि जनजातीय समुदाय सम्मान और आत्मसम्मान से निर्वाह करें: प्रधानमंत्री

एजेंसी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 1,22,100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नवरात्रि के चौथे दिन, प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में माँ त्रिपुरा सुंदरी की पावन धरती पर आने को अपना सौभाग्य कहा। उन्होंने बताया कि उन्हें कांठल और वागड़ की गंगा कही जाने वाली माँ माही के दर्शन करने का भी अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने



कहा कि माही का जल भारत के जनजातीय समुदायों के लचीलेपन और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने महायोगी गोविंद गुरु जी के प्रेरक नेतृत्व पर प्रकाश डाला, जिनकी विरासत आज भी गुंजती है और माही का पवित्र जल उस महान गाथा का साक्षी है। श्री मोदी ने माँ त्रिपुरा सुंदरी और माँ माही को नमन किया और भक्ति एवं वीरता की इस भूमि से उन्होंने महाराणा प्रताप और राजा बांसिया भील को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

श्री मोदी ने कहा कि नवरात्रि के दौरान, देश में शक्ति के नौ रूपों की पूजा की

जाती है, और बांसवाड़ा में आज का प्रमुख कार्यक्रम ऊर्जा शक्ति - ऊर्जा उत्पादन को समर्पित है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्थान की धरती से भारत के बिजली क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली परियोजनाओं के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का एक साथ आरंभ होना ऊर्जा क्षेत्र में भारत की तेजी से हो रही

प्रगति की झलक दिखाता है, जिसमें देश का हर क्षेत्र सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है और सभी राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और पारेषण लाइनों की आधारशिला रखी गई है। श्री मोदी ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और बांसवाड़ा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का एक साथ आरंभ होना ऊर्जा क्षेत्र में भारत की तेजी से हो रही



प्रगति की झलक दिखाता है, जिसमें देश का हर क्षेत्र सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है और सभी राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और पारेषण लाइनों की आधारशिला रखी गई है। श्री मोदी ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और बांसवाड़ा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का एक साथ आरंभ होना ऊर्जा क्षेत्र में भारत की तेजी से हो रही

प्रगति की झलक दिखाता है, जिसमें देश का हर क्षेत्र सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है और सभी राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और पारेषण लाइनों की आधारशिला रखी गई है। श्री मोदी ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और बांसवाड़ा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का एक साथ आरंभ होना ऊर्जा क्षेत्र में भारत की तेजी से हो रही

3 राज्यों के लिए भाजपा ने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए धर्मेंद्र प्रधान बिहार, भूपेंद्र यादव बंगाल और बैजयंत पांडा को तमिलनाडु की जिम्मेदारी

एजेंसी नई दिल्ली.
भाजपा ने गुरुवार 25 सितम्बर को बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। बिहार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को चुनाव प्रभारी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को सह-प्रभारी बनाया है। वहीं, केंद्रीय पर्यावरण, पवन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व

सोनम वांगचुक पर केंद्र का बड़ा एक्शन, लेह हिंसा के बाद रद्द किया NGO का लाइसेंस

एजेंसी। केंद्र सरकार ने लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गैर-लाभकारी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। आरोप है कि एनजीओ ने विदेशी फंडिंग से जुड़े कानून का बार-बार उल्लंघन किया। यह कदम वांगचुक के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेश में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के 24 घंटे बाद लिया गया। गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया जो सोनम वांगचुक से जुड़ी है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वांगचुक से जुड़े संस्थानों में FCRA (विदेशी अंशदान विनियमन) कानून के कथित उल्लंघन की जांच शुरू की थी। एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच कुछ समय से चल रही थी, लेकिन इस



मामले में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।
सोनम वांगचुक ने 1988 में की थी संस्था की स्थापना - स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ

लद्दाख की स्थापना 1988 में सोनम वांगचुक ने की थी। यह संगठन लद्दाख में शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में काम करता रहा है। सरकार के इस कदम के

बाद लद्दाख में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। वांगचुक पहले से ही लद्दाख की पर्यावरणीय और संवैधानिक मांगों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं।

लद्दाख में हिंसा और गृह मंत्रालय का आरोप - हाल ही में वांगचुक ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी। इस बीच बुधवार (24 सितंबर, 2025) को क्षेत्र में 1989 के बाद सबसे गंभीर हिंसा हुई, जिसमें युवाओं ने भाजपा मुख्यालय और हिल कार्सिल पर हमला किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। झड़पों में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हुई।

अरविंद केजरीवाल को जल्द मिलेगा सरकारी बंगला, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का आश्वासन

नई दिल्ली।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जल्द सरकारी बंगला मिल सकता है। गुरुवार को केजरीवाल के लिए दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि नियमों के अनुसार अगले 10 दिनों के भीतर केजरीवाल को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से वकील ने कोर्ट से मांग की कि केजरीवाल को टाइप-8 या टाइप-7 श्रेणी का बंगला आवंटित करने का आदेश दिया जाए।

रेलमंत्री ने कहा- देश भर के रेलवे स्टेशनों पर पाली में बने कुल्हड़ में बिकेगी चाय

एजेंसी। पाली।
राजस्थान के पाली में बने कुल्हड़ में देशभर के रेलवे स्टेशनों पर चाय परोसी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पाली में बन रहे मिट्टी के सिकोरे की क्वालिटी काफी अच्छी है। पाली देश के लिए रोल मॉडल बने, इसलिए यहां की महिलाओं द्वारा बनाए गए मिट्टी के सिकोरे रेलवे उपयोग में लेंगे। इससे देशभर में प्लेटफॉर्म पर सिकोरे में लोग चाय पीते नजर आएंगे, महिलाओं के रोजगार में इजाफा होगा। रेल मंत्री

गुरुवार 25 सितम्बर की सुबह करीब 6 बजे ट्रेन से पाली रेलवे स्टेशन पर उतरे। यहां उन्होंने महिलाओं की ओर से चलाए जा रहे सिलाई, चूड़ी और कुल्हड़ बनाने के उद्योगों को देखा। यहीं नहीं, हेमावास गांव में जाजम पर

काफी खुश हुए। बोले कि अच्छी बात है कि समय के साथ अपडेट हो रहे हैं। मशीनों से कम समय में अच्छी संख्या में और अच्छी क्वालिटी के कुल्हड़ पाली में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाली को रोल मॉडल बनाएंगे।

विदेश भारत को मिली बड़ी सफलता

पहली बार रेल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, 2000 किमी है रेंज

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-प्राइम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण की सबसे खास बात यह रही कि मिसाइल को पहली बार विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से दागा गया। यह परीक्षण अपनी तरह का पहला है और भारत की रणनीतिक क्षमताओं में एक नया अध्याय जोड़ता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से इसकी जानकारी साझा की और



परीक्षण का वीडियो भी जारी किया। उन्होंने बताया कि यह लॉन्चर सिस्टम बिना किसी पूर्व तैयारी के देशभर के रेल नेटवर्क पर कहीं से भी चल सकता है

और कम समय में जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। इसकी सहायता से मिसाइल की लो विजिबिलिटी में भी लॉन्चिंग की जा सकती है, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से

बेहद अहम है। राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ, सामरिक बल कमान (एसएफसी) और सशस्त्र बलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस सफल परीक्षण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास रेल आधारित मोबाइल कैनिस्टरग्राइड लॉन्च सिस्टम विकसित करने की क्षमता है। अग्नि-प्राइम मिसाइल को डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह नई पीढ़ी की मिसाइल है, जिसे कई आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है और यह उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।

कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं' यूएस ने पाकिस्तान को दिया झटका

न्यूयॉर्क, एजेंसी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द ही मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच अमेरिका ने साफ किया है कि वह कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं करेगा। इस रुख से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है।

एजेंसी के अनुसार, एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि मोदी और ट्रंप के बीच सकारात्मक रिश्तों को देखते हुए यह बैठक लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि, समय और स्थान को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारी ने कहा, "मुझे यकीन है कि आप दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। उनके बीच बेहद सकारात्मक संबंध हैं। क्राइ शिखर सम्मेलन की योजना पर काम चल रहा है। अगर इस साल नहीं तो अगले साल बैठक होगी।



कश्मीर पर अमेरिका का रुख - अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अमेरिका का भारत-पाकिस्तान को साथ बैठाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, "यह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। राष्ट्रपति तभी मदद करेंगे जब दोनों देश इसकी मांग करें। फिलहाल उनके सामने पहले से ही कई

देखता है और यूक्रेन संकट पर अधिक समन्वय चाहता है। राष्ट्र ने कहा कि भारत रुस से तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वह सस्ता है, लेकिन दुनिया में कई अन्य तेल निर्यातक देश मौजूद हैं। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि भारत हमारे साथ मिलकर तेल खरीदे। आप दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद सकते हैं, बस रुसी तेल नहीं। यही हमारा रुख है।

संकट मौजूद हैं।
मजबूत रिश्ते, कुछ तनाव भी
हाल ही में ट्रंप ने पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन पर फोन कर बधाई दी थी और उनकी सराहना करते हुए उन्हें

अच्छ दोस्त बताया था। रुस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत के प्रयासों की भी उन्होंने प्रशंसा की। इसी दौरान, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की

मुलाकात में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। फरवरी में मोदी और ट्रंप के बीच व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग को लेकर वार्ता भी हो चुकी है।

रुस-यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का बड़ा बयान, मैं राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार

एजेंसी।
राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रुस के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद वह पद छोड़ने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी प्राथमिकता एक और कार्यकाल की चाहत रखने के बजाय संघर्ष को समाप्त करना है।

जेलेंस्की ने कहा कि मेरा लक्ष्य जंग को खत्म करना है। ये टिप्पणियां उनके अब तक के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक हैं कि उनका अनिश्चित काल तक सत्ता में बने रहने का इरादा नहीं है। 2022 में रुस के पूर्ण आक्रमण के बाद वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि पाने वाले जेलेंस्की को मास्को अक्सर एक अवैध नेता के रूप में खारिज करता रहा है। इस साल की शुरुआत में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि क्रेमलिन किसी भी



संभावित शांति समझौते पर जेलेंस्की के हस्ताक्षर को स्वीकार नहीं करेगा। सर्गेई लावरोव ने बताया, जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, जब अनिश्चित काल तक सत्ता में बने रहने का इरादा नहीं है। 2022 में रुस के पूर्ण आक्रमण के बाद वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि पाने वाले जेलेंस्की को मास्को अक्सर एक अवैध नेता के रूप में खारिज करता रहा है। इस साल की शुरुआत में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि क्रेमलिन किसी भी

मध्य प्रदेश से अवैध अंग्रेजी शराब लाते समय स्कूटी सवार पकड़ाया, 96 पौआ गोवा शराब व वाहन जप्त

मनेंद्रगढ़। मध्य प्रदेश से अवैध शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक एमसीबी चंद्रमोहन सिंह के निर्देश पर दिनांक 24.09.2025 को रोड पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मध्य प्रदेश से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब परिवहन की जा रही है। सूचना के आधार पर मध्य प्रदेशड़छत्तीसगढ़ सीमा, घुटरीटोला के पास घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान स्कूटी में सवार दो व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही स्कूटी सवार पप्पू साहू उर्फ डाकू मौके से फरार हो गया, जबकि स्कूटी चालक विंधि से संघर्षरत बालक पुलिस के कब्जे में आया। स्कूटी की तलाशी लेने पर उसमें से 96 नग अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग ₹11,000/-) बरामद की गई। साथ ही, अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी वाहन को भी जप्त किया गया। पृष्ठताछ पर बालक ने बताया कि पप्पू साहू अपने होटल हेतु मध्य प्रदेश से अंग्रेजी शराब लाकर बेचता है और उसे भी इसी कार्य हेतु अपने साथ लाया था। प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना की जा रही है। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी झगराखंड दीपेश सैनी, सर्वेन अशोक साहू, प्रधान आरक्षक नीरज पट्टीयार, आरक्षक बसंत, आरजू राम मोचे, एवं सैनिक भूपेंद्र सिंह का सराहनीय योगदान रहा।



स्कूल में छुट्टी के बाद छात्रा ने छात्र का पकड़ा हाथ, शादी की जिद पर अड़ा; वीडियो वायरल

रामानुजगंज । (बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रा ने स्कूल छुट्टी के बाद एक छात्र का हाथ पकड़ लिया और शादी की जिद करने लगा। छात्र ने पहले हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं छोड़ रही थी। यह देख वहां उपस्थित छात्र-

छात्राओं और लोगों में हलचल मच गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में गांव वाले भी वहां जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों छात्र-छात्रा लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे और स्कूल में साथ पढ़ते हैं। घटना के दौरान छात्र ने खुलेआम शादी की जिद करते हुए छात्रा का हाथ पकड़ रखा था। मामला बढ़ता देख किसी ने छात्र के परिजनों को सूचना दी। थोड़ी देर में छात्र के माता-पिता मौके पर पहुंचे और दोनों को काफी समझाइश दी। इसके बाद मामला शांत हुआ और छात्र-

छात्रा को अलग किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद कई लोगों ने बना लिया, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। स्कूल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन गांव में इस घटना की चर्चा जोरों पर है। परिजन और ग्रामीणों की समय पर समझदारी से एक बड़ा विवाद टल गया।

अस्पताल में घुसा विशाल कोबरा

बलरामपुर। जिले के जरहाडीह स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब परिसर में एक विशाल कोबरा सांप दिखाई दिया। सुबह स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में सफाई के दौरान एक स्टाफ की नजर कोबरा सांप पर पड़ी। सांप को देखते ही कर्मचारियों ने अफरा-तफरी मच गई और तुरंत सभी ने अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर दौड़ लगा दी। करीब 5 से 6 फीट लंबा यह कोबरा खुले परिसर में फन फैलाए नजर आया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में भय का माहौल बन गया। तत्काल इस घटना की सूचना स्थानीय वन विभाग और स्नेक रेस्क्यू टीम को दी गई।

पूर्व विधायक उपाध्याय ने सरकार से किया सवाल- हार्ट सर्जरी बंद क्यों

रायपुर । पूर्व विधायक विकास ने 55 दिन से बायपास व ओपन हार्ट सर्जरी बंद होने पर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या मेकाहारा में ओपन हार्ट सर्जरी बंद कर प्रायवेट अस्पतालों से आपकी मिलीभगत तो नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता को कभी आयुष्मान के नाम पर तो कभी दवाईयों को लेकर तो कभी सर्जरी के नाम पर भटकनाया जा रहा है। उपाध्याय ने कहा कि मोदी की हर गारंटी छत्तीसगढ़ में शून्य है। 3 साल से ऑपरेशन थियेटर अधूरा पड़ा है, 10 करोड़ का प्रावधान केवल कागजों में ही सीमट कर रह गया है जनता के इलाज हेतु मिले फंड को छ.ग. की बीजेपी सरकार अपनी जेबों में भर रही है। एसीआई में बच्चों की हार्ट सर्जरी और ट्रांसप्लांट जो कि सालभर से प्रस्तावित है अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की साथ सरकार लगातार अपनी नाकामी प्रदर्शित कर रही है जिसे छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी देख-समझ रही है और कांग्रेस पार्टी जनता के हित में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ने कमर कस ली है। उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग गरीब व मध्यम परिवारों के लिये सभी मुफ्त व सस्ती चिकित्सा समाप्त कर रही है गरीब व मध्यम परिवारों की जान से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी श्रीधर ही स्वास्थ्य मंत्री के निवास का घेराव करेगी और छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलायेगी।



लाख पालन से बदलेगी किस्मत, जिले के कृषक मनकुराम हुए लाभान्वित

बीजापुर। जिले में लाख पालन को प्रोत्साहन देने के लिए एन सीएस और प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की पहल अब रंग लाने लगी है। भैरमगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम करैमरका के कृषक मनकुराम मरकाम ने लाख पालन से अपनी आजीविका में नई उम्मीद जगाई है। मुख्य वनसंरक्षक के निर्देशानुसार मनकुराम मरकाम को 1.10 क्विंटल लाख बीहन उपलब्ध कराया गया। दिसम्बर 2024 से जनवरी 2025 के बीच विभागीय निगरानी में उनके 7 पेड़ों पर बीहन का संचारण किया गया। समय-समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और तकनीकी सहयोग भी दिया गया। इसके परिणामस्वरूप जुलाई-अगस्त 2025 में 6.02 क्विंटल लाख का उत्पादन मिला। इसमें से 19 पेड़ों पर दोबारा 1.50 क्विंटल बीहन संचालित किया गया और शेष लाख को बिक्री कर 3.61 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित हुआ। इस सफलता ने आसपास के कृषकों को भी प्रेरित किया है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां पुसनार, कोडेली और मिरतूर के किसान भी अब स्वेच्छ से लाख पालन में रुचि दिखा रहे हैं और बीहन लगाना शुरू कर चुके हैं। इसी



कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, नवा रायपुर के निर्देशानुसार ग्राम करैमरका में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लखनऊ के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉ. ए.के. जायसवाल, उपप्रबंध संचालक अनिल कुमार बागड़े और सीनियर एग्जीक्यूटिव अविनाश हेरोम ने किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन दिया। अब 1 से 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2025 तक चयनित ग्रामों में ऑन-फील्ड प्रशिक्षण आयोजित होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा कृषक और संग्रहक लाख पालन से जुड़ें और अपनी आय एवं जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकें।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स की बेहतरीन पहल

हर महीने के दूसरे एवं चौथे बुधवार को मैग्रेटो मॉल में महिलाओं द्वारा जाए?गा लगाया बाजार

रायपुर । छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज महिला चेम्बर के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मैग्रेटो मॉल में महिलाओं द्वारा एक बाजार की शुरुआत होने जा रही है जिसमें महिलाओं द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का विक्रय किया जाए?गा,। इसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजन / नाश्ता, आचार, पापड़ गोबर द्वारा निर्मित अगरबत्ती, दिप, महिलाओं द्वारा ही घर में बनाया गया कैमिकल रहित साबुन, कपड़े या जो भी चीजें महिलाएं बनाती हैं वह विक्रय किए जाएंगे। उक्त जानकारी चैंबर अध्यक्ष डॉ. इला गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया चेंबर की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है ताकि जो महिलाएं छोटे या बड़े स्तर पर अपना कारोबार शुरू



करना चाहती हैं उनकी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल सके और यह अपने काम की शुरुआत कर सके। वहीं कोषाध्यक्ष प्रदेश महामंत्री मनीषा तारवानी

कोषाध्यक्ष नम्रता ने पहल की पूरी जानकारी दी। हर महीने लगेगा मेनेटो में बाजार समाज की हर महिला की श्वाहिश होती है कि वह भी अपना एक अलग

स्थान बनाएं और नई ऊंचाइयों को छुएं । उसकी खुद की एक पहचान हो, और यह मौका दे रहा है छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज हर महीने के दूसरे एवं चौथे बुधवार को मैग्रेटो मॉल में ग्राउंड फ्लोर पर यह बाजार लगेगा इसमें कोई भी महिला अपना स्टॉल लगा सकती है। इससे ना केवल महिलाओं का आत्म विश्वास बढ़ेगा बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी मिलेगी। कई बार महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। परंतु गृह कार्य से लेकर हर कार्य में दक्ष होती हैं, लेकिन छिप्री न होने के कारण हीनभावना से ग्रस्त हो जाती हैं और स्वयं को कमतर आंकने लगती हैं। परंतु उनके पास कुछ ऐसा हुनर होता है जिसे वह समाज में अपनी पहचान बना सकती है। चैंबर की महिला प्रतिनिधित्व के द्वारा महिलाओं के हुनर को पहचान मिलेगी साथ ही साथ उन्हें आर्थिक स्वावलंबन भी हासिल होगा।

रायपुर। भारत स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्य आयुक्त डॉ सोमनाथ यादव के निर्देशानुसार जिला संघ रायपुर के अध्यक्ष जी स्वामी जिला आयुक्त हिमांशु भारतीय के मार्गदर्शन में बालाजी विद्या मंदिर देवेंद्र नगर में सत्र 2023 ङ्क 24 और 2024 ङ्क 25 के राज्य पुरस्कार परीक्षा उत्तीर्ण रोवर रेंजर स्काउट गाइड के बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया । उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संघ के अध्यक्ष जी स्वामी ,जिषिट अतिथि सुरेश शुक्ला पूर्व जिला मुख्य आयुक्त की उपस्थिति में प्रमाण पत्र वितरण एवं समान समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व स्वागत पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ हुआ मुख्य



अतिथि जिला आयुक्त जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय ने बच्चों को एक साकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने एवं स्काउटिंग हमारे जीवन में सीखने की शक्ति विकसित होती है यह कहकर 162 विद्यार्थी सम्मानित होकर हम सबकी आने वाली पीढ़ी का हैसला बढ़ाने की बात कही। जिला संघ अध्यक्ष जी स्वामी द्वारा बच्चों को हमेशा संस्कार के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहने और छत्तीसगढ़ में स्काउटिंग की एक नई पहचान बनाने की बात

कही । पूर्व जिला मुख्य आयुक्त डॉ सुरेश शुक्ला जी द्वारा स्काउटिंग की यात्रा कभी ना कम होने नित प्रति आगे बढ़ने राज्य पुरस्कार के साथ-साथ राष्ट्रपति पुरस्कार तक जाने व शिक्षकों का आशीर्वाद हमेशा बने रहने की भाव व्यक्त करते हुए बच्चों की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी साथ ही राष्ट्रीय पत्रकार प्रकाश शर्मा जी द्वारा स्काउटिंग जीवन जीने की कला है इसे हम सबको नित प्रति आगे बढ़ते रहने की शुभकामनाएं दी।

खूबसूरत पर्यटन स्थल दनगरी घाट तक पहुंच होगी आसान

मंत्रालय में अब अधिकारी-कर्मचारियों का होगा एआई प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर गाम पोड़ीखुर्द से गाम सुलेशा के बीच दनगरी घाट तक 13.60 किमी सड़क निर्माण हेतु 18.37 करोड़ रुपए की मिली मजूरी,जल्द शुरू होगा कार्य



एक मजबूत पहचान देने के साथ ही रोजगार के नए अवसर निर्मित करना है। मुख्यमंत्री की पहल पर हाल ही में बगीचा विकासखंड स्थित दनगरी घाट तक सुगम पहुंच दिलाने के लिए गाम पोड़ीखुर्द से गाम सुलेशा के बीच दनगरी घाट तक 13.60 किमी सड़क निर्माण के लिए 18.37 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। निर्माण हेतु

आगे की प्रक्रिया जारी है। लोगों की यह बहुप्रतीक्षित मांग पूरा होने पर उनमें खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि इस पर्यटन क्षेत्र का विकास हो जाने से आसपास के ग्रामों को लाभ मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जशपुर मुख्यालय से लगभग 88 किमी दूर घने जंगलों में स्थित यह झरना ऊंची चट्टानों से तीन-चार

धाराओं में गिरता है। शांत, मनोहारी और रोमांच से भरपूर यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। मुख्यमंत्री ने 14 सितंबर को बगिया से सामुदायिक पर्यटन के तहत जशपुर के पांच ग्रामों में होम स्टे की शुरुआत की थी, जिनमें दनगरी भी शामिल है। यह नीति लागू करने का उद्देश्य रोजगार के नए अवसर निर्मित करने के साथ ही देश-दुनिया के पर्यटकों को यहां की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और लोकजीवन से परिचय कराना भी है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में मान्यता मिली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है।

रायपुर। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है कि अब मंत्रालयों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी (मध्यम स्तर और उच्च पदों पर) सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना-प्रौद्योगिकी की सहायता लेंगे। जारी आदेश जिसमें बताया गया है कि इन तकनीकी उपकरणों का उपयोग सुचारु रूप से कैसे किया जाए, इस पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नए आदेश के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम तुरंत शुरू हो जाएगा और इसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में कराया जाएगा। विभागीय स्तर पर उप सचिव, वरिष्ठ सहायक, अधीक्षण शाखा के अधिकारी, कनिष्ठ सहायकता और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत कर्मियों को इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षण का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि लगभग एक महीने की होगी और इस दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश नहीं



दिया जाएगा; यदि किसी को अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होना हो, तो उन्हें पूर्व में अनुमति लेनी होगी। इससे संकेत मिलता है कि सरकार इस कार्यक्रम को कितनी गंभीरता से ले रही है। प्रशिक्षण पहले सामाजिक विभागों, स्वास्थ्य, जल संसाधन, कृषि, शिक्षा, न्याय एवं सुरक्षा विभागों को चरणबद्ध आधार पर शामिल किया जाएगा। कभी-कभी दो विभागों का समूह एक ही दिन प्रशिक्षण में शामिल होगा ताकि समन्वय बेहतर रहे।

भाजपा द्वारा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के पदाधिकारियों की हुई घोषणा

रायपुर। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. बिशेश साहू भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव व प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय की सहमति से भाजपा जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई के जिला पदाधिकारी की घोषणा की गई है हैं जों निम्नानुसार हैं - उपध्यक्षण आनंद सिन्हा झुरानदी छुईखदान राजेश मेहता गण्डई जीवन देवांगन, टेलकाडीह निलिमा गोस्वामी खैरागढ़ प्रकाश सिंह खैरागढ़ जैनेन्द्र जधेल पदमावतीपुर छुईखदान महामंत्री नवनीत जैन छुईखदान राजाकि ताम्रकार ठकुरापारा खैरागढ़ कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल गण्डई सहकोषाध्यक्ष ललित सोनी साल्हेवारा मंत्रीगण - दीना जधेल गरि, नर्मदा ज्ञान यादव छुईखदान अरुणा सिंह विखिलदाह याददाह, जंत्री साहू कदमरारा अतरिया जमुना कुरें जोरातराई अतरिया हेमलता मंडवी साल्हेवारा प्रवक्ता - विनय देवांगन खैरागढ़ कार्यालय प्रभारी - कृष्णा वर्मा

रायपुर। 'नई शिक्षा नीति के असली अग्रदूत हैं नोडल अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स' डू उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्माउच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने नई शिक्षा नीति 2020 पर आजपं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में मालवीया मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर एवं एनईपी इम्प्लीमेंटेशन सेल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और दृष्टि देने वाली है। यह नीति न केवल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है बल्कि इसमें कौशल विकास, रोजगारपरक शिक्षा और अनुसंधान को भी प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा संस्थानों को अकादमिक उत्कृष्टता



प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और युवाओं का भविष्य और भी उज्ज्वल होगा। सरकार निरंतर प्रयासरत है कि प्रदेश का प्रत्येक युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे और अपनी प्रतिभा के बल पर समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे।

'नई शिक्षा नीति के असली

अग्रदूत हैं नोडल अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स' डू उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्माआयोजित इस कार्यशाला में नोडल अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी नीति को सफल बनाने की अंतिम कड़ी उसका जमीनी क्रियान्वयन है, और इस

जिम्मेदारी के प्रमुख सूत्रधार आप सभी हैं। नोडल अधिकारी अपने-अपने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में हृदयक2020 के प्रावधानों को चरणबद्ध ढंग से लागू करने के लिए केंद्र-बिंदु का कार्य करेंगे। कोर्स संरचना में सेमेस्टर प्रणाली, क्रेडिट ट्रांसफर, बहुविषयक विषयों का समावेश

और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की शुरुआत समयबद्ध रूप से होनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है।मास्टर ट्रेनर्स को नीति परिवर्तन के +असली मार्गदर्शक+ बताते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि वे न केवल स्वयं नीति की बारीकियों को समझें, बल्कि अपने सहकर्मी शिक्षकों को भी प्रशिक्षित और प्रेरित करें। जब भी नई मूल्यांकन प्रणाली या पाठ्यक्रम लागू होता है, शंकाएँ उठना स्वाभाविक है डू उन प्रश्नों का समाधान आपको ही करना होगा।मंत्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि बदलाव आसान नहीं होता, संसाधनों और संरचना की कमी या पुरानी व्यवस्थाओं से जुड़ी चुनौतियाँ सामने आएंगी। लेकिन उनका समाधान खोजकर ही आगे बढ़ना होगा। हम यथास्थिति बनाए रखकर आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं कर सकते। यह परिवर्तन भविष्य के लिए जरूरी है। मंत्री श्री वर्मा ने कार्यशाला को +साझा सीखने और टीमवर्क+ का मंच बताते हुए

प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे खुलकर चर्चा करें, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करें और जिन विषयों में कठिनाई हो, उन पर मार्गदर्शन लें। उन्होंने कहा कि शिक्षा में किए जा रहे सुधार केवल आदेश नहीं, बल्कि हर परिवार और हर विद्यार्थी की उम्मीदों से जुड़े सुधार हैं। +जब गरीब माता-पिता अपने बच्चे को कॉलेज भेजते हैं, तो उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर है। जब कोई छात्र नई उमंग लेकर विश्वविद्यालय आता है, तो उसके उज्ज्वल करियर की दिशा तय करना हमारा कर्तव्य है-, मंत्री वर्मा ने कहा।अंत में उन्होंने सभी से टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा डू +सा विद्या या विमुक्तये+ अर्थात वास्तविक शिक्षा वही है, जो हमें बंधनों से मुक्त करे और हमारा सर्वोत्तम व्यक्तित्व निखारे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राध्यापकगण, शोधार्थी और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सितार गुटखा घोटाले का मंडाफोड़, कारोबारी गिरफ्तार

रायपुर । राज्य कर (जीएसटी) विभाग ने गुटखा कारोबार में बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए सितार ब्रांड के गुटखा निर्माता गुरुमुख जुमनानी को गिरफ्तार कर लिया है। विभागीय जांच में सामने आया कि जुमनानी पिछले चार वर्षों से बिना जीएसटी पंजीयन के गुटखा निर्माण कर करोड़ों रुपये का कर अपवंचन कर रहा था। जीएसटी विभाग द्वारा 25 और 27 जून 2025 को दुर्ग और राजनांदगांव में की गई जांच के दौरान यह मामला उजागर हुआ। जांच में पाया गया कि वर्ष 2021 से लगातार सितार गुटखा का उत्पादन अवैध रूप से किया जा रहा था। इसके बाद विभाग द्वारा जुमनानी को समन जारी किया गया, लेकिन वह दो माह तक उपस्थित नहीं हुआ। जांच में पाया गया कि उन्होंने अप्रैल 2021 से सितम्बर 2022 तक राजनांदगांव के ग्राम मनकी और खेरागढ़ के ग्राम टेलकाडीह में,

जनवरी 2023 से जून 2023 तक रायपुर के मंदिर हसीद एवं भनपुरी में तथा जुलाई 2023 से जून 2025 तक दुर्ग के बाईडीह, जोरातराई और गानियारी क्षेत्र में फैक्ट्रियां संचालित कीं। प्रशासनिक छापों से बचने के लिए कारोबारी हर महीने फैक्ट्री का स्थान बदल देते थे तथा माल को विभिन्न नामों से गोदामों में छिपाकर बाजार में बेचते थे। जांच में यह भी सामने आया कि जुमनानी ने अपने बेटे सागर जुमनानी के नाम से कोमल फूड नामक सुपारी गोदाम दुर्ग जिले में संचालित किया। यहां से सुपारी को गुटखे में बदलकर बेचा जाता था, जबकि कागजों में केवल सुपारी बिन्नी दर्शायी जाती थी। उल्लेखनीय है कि सुपारी पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू है, जबकि गुटखे पर 28 प्रतिशत तथा 204 प्रतिशत तक का सेस लगाया जाता है। इस हेराफेरी से सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। पूर्व में भी विभाग ने मार्च 2024 में दुर्ग और राजनांदगांव में छापेमारी कर 50 लाख रुपये टैक्स जमा कराया था।

‘बढ़ती अराजकता स्वर्णिम छत्तीसगढ़ की राह में सबसे बड़ी बाधा’

स्वर्णिम छत्तीसगढ़ के लिए साहित्यकारों और विद्वानों ने किया चिंतन बैठक

रायपुर । राजधानी रायपुर में थिंक आईएसएस संस्थान में स्वयंसेवी सामाजिक संगठन पीपला वेलफेयर फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के संयोजन से साहित्यकारों और विद्वानों की बैठक-सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों, विद्वानों और पत्रकारों ने सम्मिलित होकर स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में विचार-विमर्श किया। गोष्ठी में समाज के समक्ष खड़ी विभिन्न चुनौतियों और लगातार बढ़ रही अराजकता पर चिंता जताई गई और उनके समाधान के उपाय सुझाए गए। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं और साहित्यकारों का सम्मान भी किया गया। समाज के समक्ष व्याप्त चुनौतियाँ वरिष्ठ साहित्यकार माणिक विश्वकर्मा ने कहा कि आज समाज नशावृत्ति, अनियंत्रित जनसंख्या, जल संकट, वायुप्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ध्वनि प्रदूषण जैसी अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। यदि इन पर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो ये समस्याएँ विकास की राह

में बड़ी रुकावट बन जाएंगी और स्वर्णिम छत्तीसगढ़ का सपना अधूरा रह जाएगा। नेत्र विशेषज्ञ डॉ. मनीष एस.श्रीवास्तव ने बच्चों और समाज में मोबाइल एवं तकनीक के बढ़ते उपयोग पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग बच्चों में पढ़ाई और सामाजिक व्यवहार- दोनों पर प्रतिकूल असर डाल रहा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भाषाविद् डॉ. चितरंजन कर ने बदलते समय में बच्चों के नैतिक मूल्यों, शिक्षा और संस्कार पर चिंता जताई। शिक्षा और सामाजिक मूल्यों की भूमिका पर शिक्षाविद् एवं थिंक आईएसएस के डायरेक्टर मुनेली मनोहर देवांगन ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर विचार रखते हुए कहा कि शिक्षा के बिना किसी राज्य या समाज का विकास संभव नहीं है। साहित्यकारों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में वरिष्ठ साहित्यकार रामेश्वर शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि साहित्य और पत्रकारिता समाज का आईना हैं/ इन्हीं के माध्यम से लोगों में सकारात्मक सोच और बदलाव का संदेश फैलाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ की तरफ़ी का आधार बनेंगे महतारी सदन- मुख्यमंत्री विष्णु देव

मुख्यमंत्री ने 51 महतारी सदनों का वर्चुअल शुभारंभ किया

मुख्यमंत्री ने धमतरी जिले को दी 83 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

कुरुद को नगरपालिका परिषद का दर्जा, करेली बड़ी में कॉलेज, करेली बड़ी और ग्राम खट्टी को मिलाकर नगर पंचायत और जी. जामगांव में नवीन आईटीआई सहित कई घोषणाएं

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम करेली बड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय महतारी सदन लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने करेली बड़ी में मंच से राज्य के



विभिन्न जिलों में नव निर्मित 51 महतारी सदनों का रिमोट से बटन दबाकर वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके साथ ही ग्राम संपदा एप तथा मनरेगा की समग्र जानकारी आधारित नागरिक सूचना पोर्टल का भी

शुभारंभ किया। इसके अलावा 'लखपति दीदी/महतारी सदन' और ''माँ अभियात्र'' पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों जशपुर (रंगले), बेमेतरा

(लिंझेवारा), मुंगेली (नवागांव) और दुर्ग (नगपुर) की महिला समूहों से वर्चुअल संवाद किया और उन्हें महतारी सदन तथा नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने 19 महीने के संक्षिप्त कार्यकाल में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति को सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब समूह की महिलाएँ सिलाई-कढ़ाई, सब्जी उत्पादन और स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसे अनेक कार्य महतारी सदन में कर पाएँगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना और महतारी वंदन योजना जैसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएँ संचालित कर रही है। नई औद्योगिक नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की अपार संभावनाएँ हैं।

बाढ़ आपदा पर माँक ड़िल की तैयारियों का अपर कलेक्टर ने किया निरीक्षण

रायपुर। जिले के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि 25 सितम्बर 2025, गुरुवार को प्रातः 9 बजे नवा रायपुर (परसदा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास) स्थित संध लेक में बाढ़ आपदा पर माँक ड़िल का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (नई दिल्ली), गृह मंत्रालय भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस माँक ड़िल का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन की तैयारियों का मूल्यांकन करना तथा नागरिकों को आपदा की स्थिति में त्वरित और सही प्रतिक्रिया देने के लिए जागरूक करना है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर आज अपर कलेक्टर नयता जैन (आईएसएस) ने माँक ड़िल आयोजन स्थल का निरीक्षण किया।

एक्शन टेसा ने टेसा सलाम' के साथ मनाया कारपेंटर्स मेगा मीट

दैनिक लोकशक्ति,रायपुर। छत्तीसगढ़-एक्शन टेसा भारत में एमडीएफ एचडीएचएमआर, बॉईलो एवं पार्टीकल बोर्ड जैसे इंजीनियर्स पैनल उत्पादों का सबसे बड़ा निर्माता और लकड़ी पैनल उद्योग में अग्रणी है, एक्शन टेसा ने देशव्यापी उत्सवों की एक श्रृंखला के साथ गर्व से 'मेगा कारपेंटर्स मीटिंग का आयोजन बुधवार दिनांक 24 सितंबर 2025 को होटल ग्रैंड राजपूताना रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया । आयोजन में कंपनी के जीएम. मनोज उपाध्याय जीएम, ब्रांच मैनेजर राजन दिक्षित, विदर्भ एवं छत्तीसगढ़ के समस्त सेल्स प्रतिनिधि एवं रायपुर जिला के नामी आर्किटेक्ट एवं इंटीरियर्स उपस्थित थे. सभी ने कारपेंटर्स भाईयों का स्वागत किया. राजन दिक्षित ने



आयोजन का संचालन करते हुए कहा कि ऐक्शन टेसा कारपेंटर्स के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिये समर्पित है, जिनकी कारीगरी देशभर के अनगिनत घरों एवं व्यवसायों में सुंदरता एवं कार्यक्षमता लाती है। इस मेगा मीट कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से एक्शन टेसा ने इस कार्यक्रम में उपस्थित कारपेंटर्स की कारीगरी को मान्यता देने के साथ साथ उन्हे उभरती तकनीकों और नवाचारी डिजाइन तकनीकों के बारे में जानने का एक मंच प्रदान किया. यह पहल एक्शन टेसा के ब्रांड दर्शन कोई नही ऐसा के अनुरूप है, जो अतुलनीय गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर जोर देता है। पिछले एक दशक से कंपनी इन आयोजनों के माध्यम से कारपेंटर्स के साथ निकटता के साथ काम कर रही है, उन्हे

मूल्यवान जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जिससे ब्रांड और लकड़ी के कामकाज उद्योग के साथ उनका संबंध और भी मजबूत हो रहा है। एक्शन टेसा के प्रबंध निर्देशक श्री अजय अग्रवाल जी ने इस अवसर पर वीडीडियों मेंसेज द्वारा कारपेंटर्स के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हुये कहा कि कारपेंट, इंजीनियर्स लकड़ी उद्योग की नींव है, उनकी कुशलता एवं रचनात्मकता के प्रति आभार व्यक्त किया। टेसा सलाम का अर्थ सम्मान की अभिव्यक्ति है, टेसा सलाम पहल का उद्देश्य कारपेंटर्स की स्थिति को ऊंचा उठाना है और उनके परिश्रम और कारीगरी को पहचान दिलाना है, जिससे उद्योग में उनकी भूमिका और अधिक स्पष्ट और मूल्यवान हो सके ।

रायपुर के पारागांव में आकाशीय बिजली का कहर, 27 बकरियों की मौत

रायपुर। राजधानी रायपुर से सटे नवापारा क्षेत्र के पारागांव में शुक्रवार को तेज बारिश और गरज-चमक के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। महानदी किनारे चर रही 27 बकरियां-बकरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 बकरियां घायल बताई जा रही हैं। घटना के समय गांव के कुछ चरवाहे अपने मवेशियों को नदी किनारे ले गए थे, तभी अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज बारिश शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गरज-चमक के साथ बिजली गिरी और उसके संपर्क में आने से सभी मवेशी वहीं गिर पड़े। घटना के बाद जब चरवाहे और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश बकरियां बिल्कुल शांत होकर मौत पड़ी थीं। कुछ बकरियां कराहती हुई दिखीं, जिन्हें ग्रामीणों ने तुरंत गांव लाकर प्राथमिक इलाज देने की कोशिश की। पीड़ित पशुपालकों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी जीविका का एकमात्र साधन था और इस घटना से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय राजस्व विभाग और पशु चिकित्सा टीम को जानकारी दी गई है।



मौके पर पहुंचकर टीम ने मृत मवेशियों का पंचनामा तैयार किया और घायलों का इलाज शुरू किया। सरपंच और जनपद सदस्य ने प्रशासन से आपदा राहत मद से त्वरित सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। इस घटना के बाद मौसम विभाग ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने बताया कि आगामी दिनों में भी बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। लोगों से खुले मैदान, पेड़ और नदियों के किनारे से दूर

रहने की अपील की गई है। त्रिपाठी

इतवारी-जयनगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से चलेगी

रायपुर । रायपुर दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)–जयनगर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का

परिचालन किया है। यह ट्रेन यात्रियों को कर्फम बर्थ के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। गाड़ी संख्या 08869 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)–जयनगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से 06 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 08870 जयनगरडूडहतवारी ट्रेन 18 अक्टूबर से 08 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को जयनगर से खाना होगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का वाणिज्यिक ठहराव गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा और रायगढ़ स्टेशनों पर रहेगा। इसके अलावा मार्ग में झारसुगुड़ा, राऊरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो स्टील सिटी, चंद्रपुरा, धनबाद, चितरंजन, मधुपुर, जसडीह, झांझा, जमुई, किऊल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी प्रमुख ठहराव स्थल हैं। ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिनमें 02 एसएलआरडी, 05 सामान्य, 10 स्लीपर, 02 एसी-1। और 01 एसी-1। कोच शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन सेवा से यात्रियों को त्योहार के दौरान यात्रा में सुविधा, आराम और समय की बचत होगी।

रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, गरबा आयोजन के लिए निगम से लेनी होगी अनुमति

गरबा उत्सव समिति की बैठक में कोलाहल अधिनियम का पालन करने का निर्णय

रायपुर । आगामी गरबा उत्सव को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में गरबा उत्सव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमी ध्वनि में किए जाने तथा कोलाहल ध्वनि में किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही डीजे का उपयोग रात 10 बजे के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम नंदकुमार चौबे सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। धार्मिक भावना ना हो आहत इसला रखें विशेष ध्यान बीते दिनों गणेश उत्सव के दौरान आयोजन में अश्लीलता को लेकर राजधानी में बवाल की स्थिति बन गई

थी। जिसको देखते हुए इस बार प्रशासन किसी भी प्रकार से उक्त परिस्थितियों को दोहराना नहीं चाह रहा है। इसे देखते हुए बैठक में आयोजकों से स्पष्ट रूप से गरबा में बजने वाले गीतों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। प्रशासन ने इसके लिए कहा कि ऐसे गीत या संगीत का प्रयोग न किया जाए जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। यातायात संभालेंगे स्वयंसेवक, निगम से अनुमति अनिवार्य बैठक में एडीएम उमाशंकर बंदे ने कहा कि गरबा समितियां यातायात व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति करें तथा उत्सव एवं पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। एसपी लखन पटेल ने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग एवं संबंधित थाना प्रभारी से भी अनुमति प्राप्त कर सूचना देना आवश्यक होगा। क्या कहता है।

संपादकीय

अतिक्रमण न अनूठी, न ही नई

सुप्रीम कोर्ट ने आखिर, अपने अंतरिम आदेश में पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। परंतु अदालत के समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं में जिन प्रावधानों को लेकर आपत्तियां थीं, उन पर रोक जरूर लगा दी। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत द्वारा मई के अंत में यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सरकार का मत है कि नया कानून वक्फ बोर्डे में सुधार और पारदर्शिता निश्चित करने वाला है। परंतु इस संशोधन को



विकास और विश्वास के नये धरातल पर खड़ा बस्तर

आर्भा मिश्रा

किसी भी राज्य में औद्योगिक विस्तार और निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति और जनता में सरकार के प्रति भरोसा। छत्तीसगढ़ अपने जन्म के समय से ही नक्सलवादी हिंसा से जुड़ा रहा है। खासतौर पर बस्तर का इलाका तो छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी नक्सलवादियों का गढ़ रहा है।

विकास की कमी और आम जनता पर नक्सलियों की पकड़ ने इस क्षेत्र को हमेशा पीछे रखा, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। आदिवासी बहुल इस प्रदेश में विष्णु देव साय के प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का असर अब साफ दिखने लगा है। राज्य पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ मिलकर नक्सलियों पर काफी हद तक न केवल नकेल कसी है बल्कि आदिवासी होने के नाते मुख्यमंत्री साय में राज्य के लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि बस्तर अब भय और पिछड़ेपन से निकलकर विकास और विश्वास के नये धरातल पर खड़ा है और शांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी उपेक्षा और अभाव की पहचान से जूझने वाला यह क्षेत्र अब निवेश, अवसर और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है।

मुख्यमंत्री के प्रति प्रदेश के लोगों में बढ़ता भरोसा और केंद्र सरकार के नक्सल विरोधी अभियानों से न केवल इस क्षेत्र में उद्योग और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन तक हर क्षेत्र में बदलाव दिखने लगा है, बल्कि उम्मीद और विश्वास की नई किरण जगी है। पिछले 20 महीनों में मुख्यमंत्री बस्तर के 100 से अधिक इलाकों का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों ने जनता में उनकी विसनीयता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षेत्र में नक्सलवाद पर नियंत्रण ने विकास कार्य की राह सुगम की है।

इसी का नतीजा है कि बस्तर संभाग के जगदलपुर

असंवैधानिक बताने और मुसलमानों की संपत्ति हड़पने की मंशा रखने वाला बताने वालों ने सौ से ज्यादा लोगों ने याचिकाएं लगाई थीं।

अदालत के अनुसार केंद्रीय वक्फ काउंसिल में चार से अधिक सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती जबकि राज्य के बोर्ड में तीन सदस्य होंगे। जिलाधिकारी को घोषित वक्फ संपत्ति के सरकारी होने न होने के विषय में तय करने का अधिकार भी नहीं होगा।



में पहली बार 350 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इस पर 550 करोड़ रुपये की लागत आएगी और 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसी क्रम में जगदलपुर में नवभारत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा 85 करोड़ रुपये के निवेश से 200 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और 33 करोड़ रुपये के निवेश से एक अन्य मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है।

यहां पर 7.65 करोड़ रुपये के निवेश से नमन क्लब एवं वेलनेस सेंटर भी शुरू होने जा रहा है। इन परियोजनाओं से बस्तर में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं एवं वेलनेस का विस्तार होगा और सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां की जनता भी अब हिंसा से ऊब कर इस नये बदलाव को सहर्ष स्वीकार कर रही है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और इसे ‘धान का कटोरा’ कहा जाता है, लेकिन यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार जरूरत के अनुसार नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने इस कमी को भरपाई करने की योजना बनाई और इसी के तहत बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर और कोण्डगांव जिलों में आधुनिक राइस मिल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की जा रही है। रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024 के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली या 1000 से अधिक रोजगार सृजित करने वाली परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इस नीति में औषधि निर्माण, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, आईटी एवं डिजिटल तकनीक, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस व डिफेंस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा बढ़ावा लगे, लेकिन इन सबने मिलकर भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा यात्री-अनुकूल स्थलों में से एक बना दिया है।

साल 2023 में 30 लाख से अधिक साधकों को आकर्षित किया। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के केवल छह महीनों के भीतर, 11 करोड़ से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। महाकुंभ 2025, विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समगम, में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए। केदारनाथ का पुनरुद्धार, काशी का कायाकल्प और अयोध्या का पुनर्जन्म यह दर्शाता है कि किस प्रकार आस्था और अवसरचरनाएं मिलकर यात्रा को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं।

डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज़ पर ध्यान केंद्रित करने से बुनियादी ढाँचों और पहुँच में और सुधार हुआ है। आधुनिक हवाई अड्डे, उन्नत राजमार्ग, बेहतर रेल संपर्क और निर्बाध डिजिटल बुकिंग प्रणालियों ने यात्रा को और अधिक सुविधाजनक और विश्वसनीय बना दिया है। डिजिटल ऐप्स, बहुभाषी हेल्पलाइन और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी भले ही छोटे बदलाव लगे, लेकिन इन सबने मिलकर भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा यात्री-अनुकूल स्थलों में से एक बना दिया है।

साथ ही, वीजा मानदंडों में ढील और विस्तारित ई-वीजा नीति ने विदेशी पर्यटकों के आगमन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है। सरकार ने इको-टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि भारतीय पर्यटन का भविष्य संतुलन में है - विकास के साथ-साथ स्थायित्व, बुनियादी ढाँचों के साथ-साथ विरासत और आधुनिकता के साथ-साथ परंपरा। जी-20 शिखर सम्मेलन जैसे उच्च-स्तरीय वैश्विक आयोजनों की भारत द्वारा मेजबानी ने न केवल आतिथ्य सत्कार, बल्कि सांस्कृतिक गहराई को भी प्रदर्शित किया। ऐसे अवसरों ने भारत को एक आधुनिक अर्थव्यवस्था और एक शाश्वत सभ्यता, दोनों के रूप में स्थापित किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और विशेशों से अधिक से अधिक पर्यटकों को प्रोत्साहित किया।

नीतियों से परे, मोदी जी जिस तरह से भारतीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों का समर्थन करते हैं, उसका एक व्यक्तिगत पहलू भी है। योग को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने से लेकर केदारनाथ में नंगे पैर चलने और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पानी में गोता लगाने तक, उन्होंने न केवल भाषणों के माध्यम से, बल्कि अपने अनुभवों के माध्यम से भी दुनिया को भारत से परिचित कराया है। ऐसा करके, वे स्वयं एक सांस्कृतिक राजदूत बन गए हैं, और इस विचार को पुष्ट कर रहे हैं कि ब्रांड इंडिया का निर्माण केवल बोर्डरूम या नीतिगत दस्तावेजों में

(संपादकीय + संदेश)

संवाद से समाधान तक : लेह–लद्दाख में हिंसा का सबक



ललित गर्ग

लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने व संविधान के अंतर्गत विशेष संरक्षण देने वाली छठी अनुसूची में शामिल करने के लिये चल रहे आंदोलन का हिंसक एवं विध्वंसक होना, विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प और आगजनी की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ-साथ चिन्ताजनक है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और उन्होंने लेह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी और उसके बाहर खड़े वाहनों को फूंक दिया। आमतौर पर बेहद शांत रहने वाले लद्दाख के लिए यह बहुत बड़ी घटना है। दरअसल, पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दो सप्ताह से अनशन पर थे, उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी अनशनरत थे, जिनकी तबीयत बिगड़ने से जन-आक्रोश एवं हिंसा भड़की। इस हिंसा ने अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर यह घटना वहाँ की जनता के असंतोष और बेचैनी को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर यह संकेत देती है कि लंबे समय से किए जा रहे वादे और आश्वासन क्यों अधूरे रह गए और क्यों स्थानीय लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं?

सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए के प्रावधान हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया था। तब सरकार ने वादा किया था कि हालात सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। लोगों ने सोचा था कि अब उनकी पहचान, संस्कृति और स्थानीय अधिकार और अधिक सुरक्षित होंगे। लेकिन इसके विपरीत उनकी आशंकाएं बढ़ीं। उन्हें लगा कि संघ शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली से संचालित प्रशासन स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को समझने और पूरा करने में असफल हो रहा है। इसी कारण 6 साल बाद लोगों का भरोसा और सब्र डगमगाने लगा। इसी के चलते सोनम वांगचुक को अहिंसक आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा, जो कतिपय कारणों से हिंसक हो गया। हालांकि, हिंसा के बाद वांगचुक ने अपना अनशन त्याग कर आंदोलनकारियों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की हिंसा से शांतिपूर्ण आंदोलन का मेरा संदेश आज विफ्त हो गया। अगर युवा गलत रास्ते पर जाएंगे, तो इससे हमारे वास्तविक उद्देश्य गुम हो जाएंगे। वाकई, लद्दाख के संयमी समाज को सतर्कता और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। वांगचुक का पूरा आंदोलन अहिंसक रहा है। सरकार से मतभेद होने पर भी उन्होंने बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा। उनके समर्थन में खड़े युवाओं को इसे समझना चाहिए। हिंसा से समस्या जटिल हो जाएगी। लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है, उसे देखते हुए वहां के लोगों को कानून-व्यवस्था के प्रति विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। लद्दाख का केंद्रशासित प्रदेश बनना एक नये सूरज का उदय होना है और इसका वहां के लोगों ने स्वागत भी किया था। इस क्षेत्र को कश्मीर घाटी के वचरक्ष से मुक्ति मिली थी, पर वहां के लोगों की महत्वाकांक्षा को राजनीति रंग देकर एवं संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के अधेरो में धकेल कर इसके वास्तविक उद्देश्यों को धुंधलाने की कुचेष्टा की



गई है।

हिंसा व आगजनी के बाद केंद्र शासित प्रदेश में संचारबंदी लागू की गई है। मीडिया माध्यमों से कुछ आंदोलनकारियों के मारे जाने की बात भी कही जा रही है। प्रतिक्रिया स्वरूप लेह बंद का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। यह प्रदर्शन कालांतर हिंसक प्रतिरोध में बदल गया। घटनाक्रम के बाद जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों ने हिंसा के लिये केंद्र को नशाने पर लिया है। कहा गया कि आंदोलनकारी लेह की अरिम्ता को संरक्षण देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र व लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच आगामी 6 अक्टूबर, 2025 को एक वार्ता का दौर निर्धारित था, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सदस्य शामिल होने वाले हैं। जब बातचीत होने ही वाली है, तो ऐसे विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? लेह के लोग अधूरे वायदों से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनमें यह डर है कि अगर शासन उनके हाथ में न रहा तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होगा। इसी वजह से आंदोलनकारियों की हिंसक अभिव्यक्ति सामने आई है। वास्तव में, यह पूरा आंदोलन राजनीतिक प्रवृत्ति का है। इस प्रदर्शन को साफ तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि ताजा विरोध-प्रदर्शन केन्द्र से बातचीत को अनुकूल दिशा में ले जाने की रणनीति का हिस्सा है।

लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें पूर्ण राज्य का अधिकार मिले ताकि वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें। साथ ही उनकी यह भी माँग है कि उन्हें संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए जिससे उनकी भूमि, संसाधन, परंपराएं और रोजगार सुरक्षित रहें। रोजगार के अवसरों की कमी और सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं की उपेक्षा ने इस असंतोष को और गहरा किया है। लेह और कारगिल के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। लगातार समितियाँ बनीं, बातचीत हुई, आश्वासन दिए गए, लेकिन जब ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों के भीतर अविश्वास बढ़ा। निस्संदेह, लेह चीन की सीमा से लगा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, जिसके मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना जरूरी है। एक बड़ा मुद्दा क्षेत्र के युवाओं की बेरोजगारी रही है। युवाओं की दलील है कि क्षेत्र के युवाओं को पहले जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस सेलेक्शन कमीशन में राजपत्रित अधिकारी पदों के लिये आवेदन का मौका मिलता था, जो लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बंद

महिलाएं : भारत की मौन शक्ति, जो हमें भविष्य की ओर ले जा रही हैं

डॉ. किरण मजुमदार-पॉ

जब हम अपने प्रधानमंत्री के जीवन के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो हमें उनकी यह प्रतिज्ञा याद आती है कि महिलाओं की पूरी भागीदारी के बिना भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। उनका स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है:फ़अगर मां स्वस्थ रहती है तो पूरा घर स्वस्थ रहता है। अगर मां बीमार पड़ जाती है, तो पूरा परिवार बिखर जाता है।फ़यह मानना कि महिलाओं का स्वास्थ्य ही हमारे राष्ट्रीय प्रगति की नींव है, भारत की विकास यात्रा का मुख्य आधार है।

भारत की विकास गाथा के केंद्र में महिलाएं

महिलाएं सिर्फ इस यात्रा की भागीदार नहीं हैं, बल्कि इसकी असली संचालक हैं। प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, खेलों और बायोटेक स्टार्ट-अप में उनके मौन लेकिन प्रभावशाली कार्य हमारे भविष्य को गढ़ रहे हैं। उन 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं के बारे में सोचें, जो भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं, जो अक्सर प्रकोप के दौरान सबसे पहले मदद पहुंचाती हैं या फिर आईसीएमआर, एनआईवी और एप्स की महिला वैज्ञानिकों पर विचार करें, जिन्होंने 2020 में सार्स - सीओवी-2 वायरस को अलग करने में मदद की और भारत के स्वदेशी टीकों का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके कारण दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 2 अरब से अधिक टीकाकरण किए गए।1

भारत की 62.9 प्रतिशत महिला कार्यकर्ता कृषि में हैं, और अब इनमें से कई को सूखा-रोधी व फसल सुरक्षा जैसे बायोटेक समाधान अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया है।2 बायोटेक उद्यमिता में भी महिलाएं सस्ते डायग्नोस्टिक, जीनोमिक्स और वैक्सीन नवाचार जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट-अप की अगुवाई कर रही हैं। ये कोई अकेली कहानियां नहीं हैं, ये भारत की नारी शक्ति का जीता जागता सबूत हैं।

नीतिगत और संस्थागत समर्थन

महिलाओं की क्षमता को उभारने में सरकारी पहल निर्णायक रही हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर मिशन शक्ति तक, संसद में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और जन धन योजना के जरिए आर्थिक शक्तिकरण- महिला-प्रधान विकास की मजबूत रूपरेखा तैयार हो चुकी है।

54 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं, जिनमें लगभग 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। वित्तीय समावेशन का ऐसा स्तर दुनिया भर में शायद ही कभी देखा गया हो।

मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋणों से से लगभग 70 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम जल्द ही यह सुनिश्चित करेगा कि संसद की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों।

लोकशक्ति

www.lokshakti.in

लोकशक्ति



हो गया। स्थानीय युवा अब केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की स्पर्द्धा में टिक पाने में दिक्कत महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय नौकरियों में युवाओं के लिये कोई विशेष अभियान भी नहीं चला। जिससे बेरोजगारों में खासा रोष व्याप्त रहा है।

आंदोलनकारी इसके अलावा कारगिल व लेह को लोकसभा सीट बनाने और स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की भी मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची में ऐसी स्वायत्त व अधिकार संपन्न प्रशासनिक इकाइयों का प्रावधान है, जिनके पास जल-जंगल व उद्योगों को लेकर क्षेत्र की संस्कृति व संरक्षण हेतु निर्णय करने का अधिकार होता है। लोग यह महसूस करने लगे कि उनकी जान-माल की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। लद्दाख की जनता के भीतर असुरक्षा की भावना इसलिए भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमि और संसाधनों पर बाहरी दखल बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएँ जैसे हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स कमजोर कर दी गई हैं और महत्वपूर्ण फैसले केंद्र के हाथ में केंद्रित हो गए हैं। इससे यह भावना गहराती है कि स्थानीय समाज की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जब लंबे समय तक विश्वास और संवाद की कमी बनी रहती है तो जनता के धैर्य का बाँध टूट जाता है। यह सिर्फराज्य का दर्जा पाने की माँग नहीं है बल्कि यह आत्म-नियंत्रण, पहचान और न्याय पाने की जद्दोजहद है।

लद्दाख की जनता यह चाहती है कि उनके अधिकारों को संवैधानिक गारंटी मिले, उनके संसाधनों की सुरक्षा हो और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। यदि सरकार ने पहले जो आश्वासन दिए थे, उन्हें समयबद्ध और स्पष्ट तरीके से लागू कर दिया जाता तो शायद स्थिति यहाँ तक न पहुँचती। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार संवाद और विश्वास बहाली की दिशा में ठोस कदम उठाए। संवैधानिक गारंटी देकर, स्थानीय प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाकर, रोजगार और शिक्षा की योजनाओं को मजबूती देकर ही इस असंतोष को शांत किया जा सकता है। लद्दाख की जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके हित सुरक्षित हैं, तभी हिंसा और आक्रोश का माहौल शांति और भरोसे में बदला जा सकेगा। लोगों में यह विश्वास पैदा करना जरूरी है कि फैसलों में लद्दाख के हितों का ख्याल रखा जाएगा। इसका सबसे बेहतर तरीका है पारदर्शिता। वहाँ, जनता को भी समझना होगा कि सरकार के लिए हर मांग मानना और तुरंत मानना संभव नहीं होता।

यह निजी विचार है।

जिससे नीति निर्माण में उनकी आवाज़ सुनिश्चित होगी।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार: वैश्विक संदर्भ में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय महिलाएं सचमुच सितारों तक पहुंच रही हैं। इसरो में महिलाओं ने चंद्रयान-2 और मंगलयान जैसी मिशनों में निदेशक की भूमिका निभाई, जिससे भारत की अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरती छवि सामने आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी के मामले में दुनिया में अग्रणी है:

भारत में 43 प्रतिशत एसटीईएम स्नातक महिलाएं हैं, जबकि अमेरिका में 34 प्रतिशत, यूरोपीय संघ में 32 प्रतिशत और ओईसीडी देशों में औसतन 33 प्रतिशत फिर भी, वैज्ञानिक संस्थानों में केवल 19 प्रतिशत वैज्ञानिक, इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट ही सीधे अनुसंधान और विकास से जुड़े हैं, जिससे यह जरूरी हो जाता है कि शिक्षा में मिली सफलता को कार्यस्थलों पर भी प्रतिनिधित्व में बदला जाए।5

सरकार के बायोकेयर और वाइज किरण जैसे कार्यक्रमों ने करियर ब्रेक के बाद लौटें महिला वैज्ञानिकों को फिर से नवाचार शुरू करने का अवसर दिया है। हाल ही में बीआईएआरएसी ने 75 से अधिक महिला बायोटेक उद्यमियों को सम्मानित किया, जो नई पीढ़ी की महिला नेतृत्व का संकेत है। वैश्विक स्तर पर बायोटेक नेतृत्व पदों पर महिलाएं 20 प्रतिशत से भी कम हैं, ऐसे में भारत की यह प्रगति विज्ञान उद्यमिता में समावेशिता के नए मानक तय कर सकती है।

भविष्य की ओर: अग्रणी महिलाएं

विज्ञान-आधारित विकास का भविष्य उन महिलाओं द्वारा गढ़ा जाएगा जो जीनोमिक्स, मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक्स, बायोलॉजिक्स और सटीक उपचार को आगे बढ़ाएंगी। वे जैव प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं, नियामक पारिस्थितिकी प्रणालियों और जमीनी स्तर के स्वास्थ्य वितरण नेटवर्क का नेतृत्व करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि किफायती चिकित्साएं दूर-दराज के गांवों तक भी पहुंचें। एक गैराज लैब से लेकर एक वैश्विक बायोलॉजिक्स कंपनी बनाने तक की मेरी अपनी यात्रा ने मुझे सिखाया है कि नवाचार केवल बोर्डरूम में ही जन्म नहीं लेता। यह जमीनी स्तर से जन्म लेता है और मेहनत व धैर्य से आगे बढ़ता है, चाहे वह तकनीशियन हो, शोधकर्ता (पोस्ट-डॉक) या स्वास्थ्यकर्मी। जब उन्हें अवसर और पहचान मिलती है, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।

भारत के लिए एक अहम मोड़

जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा बनाए रखने और अंतरिक्ष व डिजिटल तकनीक के नए आयाम आने वाले दशकों में भारत की प्रगति को परिभाषित करेंगे। प्रधानमंत्री की दृष्टि स्पष्ट है: महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि इस भविष्य की सह-निर्माता के रूप में देखा जाना चाहिए।

आह्वान

अब समय आ गया है कि सभी क्षेत्रों में नेतृत्व यह सुनिश्चित करे कि महिला वैज्ञानिक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी और उद्यमी पूरी तरह से दिखाई दें, उन्हें पर्याप्त संसाधन मिलें और वे पूरी तरह सशक्त हों। जब ऐसा होगा, तो भारत न केवल अपना वादा पूरा करेगा बल्कि दुनिया की उम्मीदों से भी आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि हम सभी द्वारा निर्मित और महिलाओं के नेतृत्व वाला भविष्य अजेय होगा।

यह निजी विचार है।

जहाज निर्माण, समुद्री क्षेत्र में वित्तपोषण और घरेलू क्षमता को मजबूत करने के लिए व्यापक चहुंमुखी पहल

मंत्रिमंडल ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी

जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को कुल 24,736 करोड़ रुपये की राशि के साथ 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया गया

20,000 करोड़ रुपये के समुद्री क्षेत्र निवेश कोष के साथ समुद्री विकास निधि को मंजूरी दी गई

19,989 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जहाज निर्माण विकास योजना का लक्ष्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को 4.5 मिलियन सकल टन भार तक विस्तारित करना है

पीआईबी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में समुद्री क्षेत्र के सामरिक और आर्थिक महत्व को स्वीकार करते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के जहाज निर्माण और समुद्री इको-सिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी। यह पैकेज घरेलू क्षमता को मजबूत करने, दीर्घकालिक वित्तपोषण में सुधार करने, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ एक मजबूत समुद्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने हेतु कानूनी, कराधान और नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए डिजाइन किए गए चहुंमुखी पहल को प्रस्तुत करता है। इस पैकेज के तहत, जहाज निर्माण वित्तीय सहायता



योजना (एसबीएफएस) को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा और इसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपये होगी। इस योजना का उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है और इसमें 4,001 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है। सभी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने हेतु 25,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ समुद्री विकास निधि (एमडीएफ) को मंजूरी दी गई है। इसमें भारत सरकार की 49 प्रतिशत भागीदारी वाला 20,000 करोड़ रुपये का समुद्री निवेश कोष और ऋण की प्रभावी लागत कम करने तथा परियोजना की बैंकिंग क्षमता में सुधार हेतु 5,000 करोड़ रुपये का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल

है। इसके अलावा, 19,989 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) का उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन भार तक बढ़ाना, मेगा जहाज निर्माण समूहों को सहायता प्रदान करना, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करना और जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए बीमा सहायता सहित जोखिम कवरेज प्रदान करना है। इस समग्र पैकेज से 4.5 मिलियन सकल टन भार की जहाज निर्माण क्षमता का विकास होने, लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होने और भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। अपने आर्थिक प्रभाव के अलावा, यह पहल महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री मार्गों में अनुकूलन लाकर राष्ट्रीय, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। यह भारत की भू-राजनीतिक दृढ़ता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को भी सुदृढ़ करेगा, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा और भारत को वैश्विक नौवहन एवं जहाज निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। भारत का एक लंबा और गौरवशाली समुद्री इतिहास रहा है, जिसमें सदियों पुराना व्यापार और समुद्री यात्रा इस उपमहाद्वीप को दुनिया से जोड़ती रही है। आज, समुद्री क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, जो देश के लगभग 95 प्रतिशत व्यापार को मात्रा के हिसाब से और 70 प्रतिशत मूल्य के हिसाब से सहारा देता है। इसके मूल में जहाज निर्माण है, जिसे अक्सर «भारी इंजीनियरिंग की जननी» कहा जाता है, जो न केवल रोजगार और निवेश में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वतंत्रता और व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुकूलन को भी बढ़ाता है।

सिक्किम अद्भुत प्रदेश, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर– श्री शिवराज सिंह

पीआईबी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फल के अंतर्गत सिक्किम के बर्मीओक स्थित बागवानी महाविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन और वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशाला का वचुंअल उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री भागीरथ चौधरी, सिक्किम के कृषि मंत्री श्री पूरन कुमार गुरुंग, कुलपति डॉ. अनुपम मिश्रा सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भले ही आज मैं सशरीर सिक्किम में मौजूद नहीं हूँ लेकिन मेरी अंतरात्मा बर्मीओक के बागवानी महाविद्यालय के



नवनिर्मित भवन में आपके बीच ही है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के नाते श्री भागीरथ चौधरी वहां उपस्थित हैं। श्री चौहान ने कहा कि नवनिर्मित भवन का निर्माण 52 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। इसके निर्माण से सिक्किम के हमारे बेटे-बेटियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि सिक्किम अद्भुत प्रदेश है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सिक्किम की जलवायु अद्भुत है। सिक्किम की धरती पर एवोकाडो, कीवी, बड़ी इलायची, आर्किड सहित सब्जियों में अदरक, हल्दी, टमाटर और गोभियों की व्यापक संभावनाएं हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, बांस, गैर-परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने के कारण सिक्किम की बागवानी गतिविधियों में बहुत विविधता आई है। उन्होंने कहा कि सिक्किम एक जैविक राज्य है। केमिकल फर्टिलाइजर से दूर शुद्ध उत्पाद यहां के किसान सिक्किम ही नहीं, पूरे देश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं यहां के किसान भाई-बहनों को प्रणाम करता हूँ। श्री शिवराज सिंह चौहान ने

कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खेती तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे पर्वतीय राज्यों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में खेती को आगे बढ़ाने में भारत सरकार अपनी ओर से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। यहां की अनुपम जलवायु के कारण सिक्किम की जो विशेषताएं हैं, उनका कैसे हम और ज्यादा दोहन कर पाएं, इसकी हम कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में जैविक उत्पादन बढ़ रहा है और यह आज की ज़रूरत भी है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 6 सूत्र हैं। इसमें उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। इसके साथ ही कृषि का विविधीकरण।

निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया

पीआईबी। निर्वाचन आयोग ने पिछले छह महीनों में चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 29 महत्वपूर्ण पहल की हैं। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने अपनी 30वीं पहल के अंतर्गत देरी को कम करने और स्पष्टता बढ़ाने के लिए डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। (अनुलग्नक) मतगणना प्रक्रिया के दो प्रमुख भाग हैं: डाक मतपत्रों/इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्रों (ईटीपीबी) की गिनती; ईवीएम के माध्यम से गिनती। मतगणना के दिन डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे और ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होती है। पूर्व निर्देशों के अनुसार डाक मतपत्रों की गिनती के चरण की पवाह किए बिना सैद्धांतिक रूप से ईवीएम की गिनती जारी रह सकती है और डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने से पहले इसके पूरा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक) के लिए घर से मतदान हेतु आयोग द्वारा हाल ही में की गई पहलों के मद्देनजर डाक मतपत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।



यद्यपि डाक मतपत्रों की गिनती आमतौर पर ईवीएम की गिनती से पहले पूरी हो जाती है। फिर भी मतगणना प्रक्रिया में एकरूपता और अत्यधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने निर्णय लिया है कि अब से ईवीएम/वीवीपेट की गिनती का अंतिम से पहले वाला (दूसरे अंतिम) दौर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद ही मतगणना केंद्र पर शुरू किया जाएगा। जहाँ डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जहाँ डाक मतपत्रों की संख्या अधिक हो तो वहाँ रिटर्निंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त संख्या में टेबल और मतगणना कर्मचारी मौजूद हों ताकि कोई देरी न हो और मतगणना प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया जा सके।



केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।



छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साह रायपुर में अंगूली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के कार्यान्वयन पर फीडबैक लेने के लिए एक खुदरा स्टोर का दौरा करते हुए।

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
HASDEO BARRAGE W/M DIVISION, RAMPUR/ KORBA (C.G.)
e-PROCUREMENT TENDER NOTICE
eProcurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>
(THIRD CALL)

NIT No.: 05/SAC/2025-26

Dated: 24-09-2025

Online Tenders are invited for the following works up to 13-10-2025 at 17.30 Hour

SystemTender No	Name Of Work	Amount
System No-176373	Repair of C.C. Lining of Hasdeo Right Bank Canal from R.D. 5 KM to R.D. 10 K.M. under Hasdeo Bango Project at Korba Distt.	Rs. 286.45 Lakhs Tender Invited As Per SOR of August 2022

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh Integrated e-Procurement Portal (<https://eproc.cgstate.gov.in>) from Date 01-10-2025, at 17.31 Hours.(IST) onwards.
NOTE :- All eligible interested contractors/bidders are mandated to get enrolled on the Integrated e-procurement portal (<https://eproc.cgstate.gov.in>) and get approval on specific vendor class from PWD under Centralized Contractor Supplier Registration in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process. Other terms and condition of this tender visit WRD website <https://eproc.cgstate.gov.in> under Live Tender available.
Other terms and condition of this tender visit WRD website <https://eproc.cgstate.gov.in> under Live Tender available

G-252603721/4

Executive Engineer
Hasdeo Barrage W/M Division,
Rampur / Korba (C.G.)

स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत एक दिन एक घंटा एक साथ अभियान

पीआईबी

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत «एक दिन एक घंटा एक साथ» अभियान में शामिल हुआ, पूरे परिसर में स्वच्छता में चैंपियन बना

स्वच्छ राष्ट्र के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का एक उत्साही पहल करते हुए आयुष मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) ने व्यापक स्वच्छता ही सेवा - 2025 अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक पहल «एक दिन एक घंटा एक साथ» कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल और उसके आसपास स्वच्छता, सफाई और अनुशासन की एक सतत संस्कृति को बढ़ावा देना है, और इस बात पर बल देना है कि सामूहिक कार्रवाई की शक्ति ही सार्थक बदलाव ला सकती है। इस वर्ष की



थीम विशेष रूप से देश के उत्सवों की उल्लासमय भावना को स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने के लिए तैयार की

गई है। अभियान के तहत भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग ने अपने परिसर और

आसपास के आवासीय क्षेत्रों में एक विशाल रैली और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। कर्मचारियों ने भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग परिसर के पॉकेट 1 से पॉकेट 3 तक, साथ ही परिसर से स्टेट आसपास के इलाकों में भी सफाई अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग के निदेशक ने कर्मचारियों को संबोधित किया और कार्यस्थल के अंदर और समुदाय में स्वच्छता और सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। निदेशक ने कर्मचारियों को अपने आस-पास के वातावरण की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया और यह भी बताया कि स्वच्छ भारत के व्यापक लक्ष्य को साकार करने के लिए टीम वर्क और सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष से समाज प्रमुखों ने की मुलाकात

जांजगीर-चाम्पा। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 45 से 50 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय नौकरी एवं निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षण प्रदान किया जा रहा है लेकिन पिछड़ा वर्ग को उनके जनसंख्या के अनुपात में अभी तक आरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। पूर्व सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर स्वीकृति हेतु राज्यपाल को भेजा गया जो कि आज दिनांक तक लंबित है। जनसंख्या के अनुपात में दिलाये जाने हेतु जापन दिया गया ।

विभिन्न समाज के प्रमुख सामाजिक बात को रखें जिसमें कन्हैया राठौर कनौजिया राठौर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज में बालिका शिक्षा ,मृत्युभोज को सिमित मात्रा में करने, विवाह विच्छेद को सामाजिक स्तर पर सुलझाने आदि सामाजिक बातों को रखा । गिरधारी यादव के द्वारा विभिन्न समाज प्रमुखों का प्रतिमाह सामाजिक बैठक आयोजित करने की बात रखी , पटेल मरार समाज से बसंत पटेल ने अपनी



बात रखी । ओबीसी महासभा से हरिश्चंद्र साहू ने 27त आरक्षण एवं जनगणना में ओबीसी का कालम जोड़ने अपील की जिससे ओबीसी की जनगणना हो सके । ओबीसी आयोग से आए हुए अध्यक्ष आर.एस.विश्वकर्मा,आई.ए.एस. नीलांबर नायक, यशवंत सिंह वर्मा,

बलवाऊ राम साहू, हरिशंकर यादव, श्रीमती शैलेन्द्री परगनिहा, कृष्णा गुप्ता छग. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ओबीसी समुदाय की प्रमुख कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का अवलोकन करने के लिए यहां पहुंचे थे । विभिन्न समाज के लोग यहां उपस्थित रहे और कार्यक्रम का निष्पादन किया जिसमें प्रमुख रूप से हरीश कुमार गोपाल जिलाध्यक्ष ओबीसी महासभा, हरिश्चंद्र साहू प्रदेश सहसचिव ओबीसी महासभा, अमित यादव यादव समाज,शिव प्रसाद राठौर , रामानुज राठौर, परमेश्वर निर्मलकर, गिरधारी यादव यादव समाज, कन्हैया राठौर कनौजिया राठौर समाज, हेमचंद्र राठौर ,सत्यनारायण पटेल मोतीलाल पटेल, बसंत पटेल, गोपीचंद बरेट, संतोष बरेट, किशोर साव, राजेंद्र बरेट आदि ओबीसी समाज के जिला प्रतिनिधि एवं जिला प्रमुखों का भेंट वार्ता मुलाकात हुआ ।

मयंक शुक्ला सहायक संचालक व श्रीमती रिचा अग्रवाल लेखापाल की सेवा समाप्त

जांजगीर-चांपा /

लाईवलीहुड कालेज में उपस्थिति के संबंध में फिंगरप्रिंट क्लोन बनाकर अनुपस्थित छात्र-छात्राओं का बायोमैट्रिक मशीन में उपस्थिति दर्ज करते वीडियो के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायत के जांच हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन उपरांत जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जांच में उक्त कृत्य की सत्यता प्रमाणित हुई तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये गये एवं आरोप प्रमाणित पाये गये। श्री मयंक शुक्ला सहायक संचालक (संविदा) व श्रीमती रिचा अग्रवाल लेखापाल (संविदा) लाईवलीहुड कालेज के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने तथा उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के विरुद्ध होने के कारण उनको एक माह का वेतन भुगतान करते हुए उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है।

पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं - राजेश्री महन्त



भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ एवं जिले की देवी मंदिरों में किए पूजन दर्शन

जांजगीर चांपा / छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज शारदीय नवरात्र में जिला जांजगीर चांपा के अनेक स्थानों में विराजित माता दुर्गा भवानी के मंदिरों में दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने ग्राम खरौद में सौराईनदाई मंदिर, मनका दाई मंदिर, ग्राम सलखन एवं महंत में चंडीदाई

मातेश्वरी, ग्राम खोखरा में मनका दाई मंदिर, ग्राम बिरां में चंडी दाई, कंकालीन दाई, महामाया देवी मंदिर तथा ग्राम केरा में चंडी दाई, महामाया देवी एवं ठाकुर देव भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित हुए वे ग्राम तुप्पा के साहू परिवार में आयोजित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में भी सम्मिलित हुए। यहां उन्होंने श्रोता समूह को संबोधित करते हुए कहा कि- हम सभी का सौभाग्य है कि

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और हमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। साहू परिवार ने जिस उद्देश्य की मनोकामना के लिए यह आध्यात्मिक आयोजन किया है माता दुर्गा भवानी से प्रार्थना है कि उसे पूर्ण करें।

उन्होंने कहा कि धर्म शास्त्रों में लिखा है कि भले ही पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता

नहीं हो सकती! इन अनेक कार्यक्रमों में राजेश्री महन्त जी महाराज के साथ कमलेश सिंह, बृजभान सिंह, राजू राणा, सुनील सिंह राणा तथा सुबोध शुक्ला, गोविंद यादव, शरद शर्मा, अशोक आदित्य, जगदीश यादव, भारत कश्यप, रामकृष्ण कश्यप, अवधेश सिंह, उपेंद्र तिवारी, पवन चतुर्वेदी, बसंत पवार, दिलदार खान संतोष साहू, रामखिलान तिवारी, ईश्वर देवांगन, माधुरी

नरेश आदित्य, एलडी आदित्य, तोषन महाराज, रामचरन साहू, रामनारायण साहू मीडिया प्रभारी निर्मल दास वैष्णव, हर्ष दुबे सहित अनेक गणमान्य नागरिक गण सम्मिलित हुए। उल्लेखनीय है कि अपने इस आध्यात्मिक यात्रा के बीच राजेश्री महन्त जी महाराज बम्हनीडीह में शोक संतुप्त सहारे परिवार से भी सौजन्य भेंट मुलाकात कर पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित किए।

शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित

जांजगीर-चांपा / छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा) अकलतरा ने विकासखंड अकलतरा के ग्राम करूमहू के शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन के लिए 10 अक्टूबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा ने बताया कि विकासखंड अकलतरा के ग्राम करूमहू के ग्राम पंचायत के समस्त स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत, सेवा सहकारी समिति आदि से शासकीय उचित मूल्य दुकान प्राप्त करने हेतु इच्छुक संस्था, समूह से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ-साथ संलग्न के रूप में समूह का पंजीयन प्रमाण पत्र, वर्तमान माह से विगत एक वर्ष खाता स्टेटमेंट की छायाप्रति के साथ 10 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र के साथ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रा अकलतरा में प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।



जांजगीर चांपा /

छाता जंगल में जुआ खेलने वालों के विरुद्ध बलौदा पंतोरा पुलिस की छापामार कार्रवाई

जांजगीर चांपा / छाता जंगल में छापामार कार्रवाई करते हुए बलौदा पंतोरा पुलिस ने जुआरियों के 17 मोटर साइकिल जब्त किए हैं जबकि जुआरी भाग निकलने में सफल रहे । ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में जिले में जुआ सट्टा खेलने एवं खिलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है । इसी क्रम में थाना बलौदा पुलिस को मुखबिर सूचना मिला की बलौदा क्षेत्र के छाता जंगल में कुछ लोग जुआ खेलने के लिए जंगल अंदर मोटर सायकल से गये है । उक्त सूचना पर थाना बलौदा एवं चौकी पंतोरा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जंगल में छापामारी किया गया जहां जंगल के अंदर अलग - अलग स्थानों झाड़ियों की आड में मोटर सायकल खडा हुआ मिला जंगल अंदर पुलिस को आते देख जुआ खेल रहे जुआडियान भाग गए, जंगल से कुल 17 मोटर सायकल को जप्त किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी बलौदा निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव एवं चौकी प्रभारी पंतोरा उनि दिलीप सिंह एवं थाना बलौदा व चौकी पंतोरा स्टाप का विशेष योगदान रहा।

मॉकड्रिल रेस्च्यू टीम ने घटनास्थल पर लोगों की जान बचाने किया अभ्यास

शिवरीनारायण एवं कुकदा रिंगनी में बाढ़ आपदा से बचाव के लिए किया गया मॉकड्रिल



जांजगीर-चांपा /

भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के सहयोग से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिले में बाढ़ आपदा से बचाव के लिए शिवरीनारायण स्थित महानदी नदी के बाबाघाट एवं कुकदा रिंगनी के कंजी नाला में विशेष मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। मॉकड्रिल के दौरान अपर कलेक्टर श्री आर.के. तंबोली, एसडीएम जांजगीर श्री सुब्रत प्रधान, एसडीएम पामगढ़ श्री देवेन्द्र चौधरी, एसडीएम चांपा श्री सुमित बघेल सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी व स्थानीय नागरिक

मौजूद रहे। मॉकड्रिल में मोटर बोट, स्क्यूबा डायविंग, लाइफ जैकेट, सर्च लाइट एवं विभिन्न प्रकार के बचाव उपकरण का प्रयोग कर बाढ़ बचाव कार्य का लाइव डेमो (मॉकड्रिल) किया गया। इसमें नदी में डूबते व्यक्तियों को सुरक्षित निकालना, तेज बहाव में फंसे लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, क्षतिग्रस्त इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालना तथा आपदा प्रबंधन में आधुनिक बचाव उपकरणों का प्रयोग कर प्रदर्शित किया गया। मॉकड्रिल में बताया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के घरों में उपलब्ध होने वाली सामग्रियों जैसे गोल

बर्तन, ड्रम, मटका, ट्यूब, प्लास्टिक बॉटल, इत्यादि सामग्रियों का राफ्ट (तैरती हुई संरचना) बनाना एवं पीने के पानी की बोतल को एयर टाइट कर लाइफ जैकेट बनाकर डूबते हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इसके अलावा अग्निशमन टीम ने आग लगने के बाद उत्पन्न होने वाली अत्यधिक गर्मी को नियंत्रित करने के लिए पानी के छिड़काव के माध्यम से तापमान को संतुलित करने का अभ्यास किया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को आपदा की स्थिति में उठाए जाने वाले जरूरी कदमों की जानकारी भी दी गई।

बोलेरो वाहन से 55 किलो 320 ग्राम गांजा जब्त- दो आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल

जांजगीर चांपा /

बोलेरो वाहन से 55.320 ग्राम गांजा जब्त कर शिवरीनारायण पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है । घटना का विवरण इस प्रकार है कि थाना शिवरीनारायण पुलिस को दिनांक 24 सितंबर 25 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि महासमुंद जिले से बोलेरो वाहन क्रमांक छत्त-06 -तस्-0190 में भारी मात्रा में गांजा लेकर बिलासपुर की ओर भेजा जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के

कुशल मार्गदर्शन तथा एसडीओपी चांपा यदुमणि सिदार के नेतृत्व में थाना प्रभारी शिवरीनारायण द्वारा विशेष टीम गठित कर नेहरू बालोद्यान, शिवरीनारायण के पास घेराबंदी की गई। पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई के दौरान* पुलिस ने बोलेरो वाहन को पायलटिंग कर रही एक काले-नीले रंग की बजाज पल्सर वाहन क्रमांक छत्त-06- तड्डू-8441 को रोका। तत्पश्चात बोलेरो वाहन को रोककर दोनों वाहनों के व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपीगण में कमल कुमार भोई पिता नेत्रमणि भोई, उम्र 25 वर्ष, निवासी बामराडीह थाना

बसना जिला महासमुंद ,आशीष नंद पिता सुकदेव नंद उम्र 38 वर्ष निवासी गेरांभाठा थाना बसना जिला महासमुंद शामिल है जबकि अन्य दो अज्ञात आरोपी एवं महिला आरोपी की तलाश जारी है।

आरोपियों का कृत्य धारा 20 (बी), 29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दंडनीय पाया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया एवं शेष आरोपियों की तलाश जारी है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा।



बलिकाओं की अभिरुचि एवं समस्याओं के निराकरण हेतु जिज्ञासा बॉक्स स्थापित



जांजगीर-चांपा / कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं के सर्वांगीण विकास एवं उनके विचारों, समस्याओं तथा सुझावों को जानने के उद्देश्य से जिले के शासकीय विद्यालयों में जिज्ञासा बॉक्स की स्थापना की गई है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के समन्वय से विद्यालयों में जाकर बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया तथा उन्हें जिज्ञासा बॉक्स की कार्यप्रणाली और उद्देश्य के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बालिकाओं को प्रेरित किया गया कि वे बिना नाम उजागर किए, निरुसंकोच अपनी बात, समस्या या सुझाव बॉक्स में डालें। इस पहल को बालिकाओं से सकरात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और उनमें विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई, नवा बिहान, सखी वन स्टॉप सेंटर, मिशन शक्ति सहित महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सहायता तथा सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। साथ ही जागरूकता सत्र का आयोजन कर बालिकाओं को इन सेवाओं का लाभ उठाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले के 56 शासकीय विद्यालयों में जिज्ञासा बॉक्स स्थापित किया गया है। बालिकाओं द्वारा जिज्ञासा बॉक्स में पत्र डालने की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि यह पहल उनके आत्म-प्रकाशन और विकास का प्रभावी माध्यम बन रही है।

खास खबर

निगम के जौन कार्यालयों में 25 सितम्बर को लगेगा सत्यापन शिविर

कोरबा)। नगर पालिक निगम कोरबा के सभी 07 जौन कार्यालयों में 25 सितम्बर 2025 को सेवा पखवाड़ा दिवस शिविरों का आयोजन कार्यालयीन समय पर किया जाएगा। इन शिविरों में सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित केन्द्रीय पेंशन योजनाओं यथा-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना के हितग्राहियों का सत्यापन किया जाएगा तथा नवीन पेंशन स्वीकृति हेतु फर्म भराए जाएंगे एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड हेतु पंजीयन किया जाएगा। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा इन योजनाओं के हितग्राहियों से उक्त शिविर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचने का आग्रह किया गया है।



कोरबा में धर्मांतरण के मुद्दे पर हुआ हंगामा

कोरबा । कोरबा के वार्ड क्रमांक 19, पथरीपारा में मंगलवार की रात धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि एक घर में पूजा-पाठ और धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियां की जा रही थीं, जिसकी सूचना मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और इसका कड़ा विरोध किया। बताया जा रहा है कि पथरीपारा के टावर के पास एक घर में कुछ लोगों द्वारा पूजा-पाठ और धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियां की जा रही थीं। वहां पादरी की भी उपस्थिति होना कहा जा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष रूटीन प्रार्थना करना कह रहा है। घटना की जानकारी सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांत करवाया। पिलहाल, मामले की जांच जारी है और पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है। घटना के बाद देर रात क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि मामले की कार्रवाई की जाएगी।

जिला पुनरीक्षा समिति की बैठक 26 को

कोरबा । मार्गदर्शी बैक योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय सलाहकार समिति, जिला पुनरीक्षा समिति की बैठक 26 सितंबर को अपराह्न 3.15 बजे सीईओ जिला पंचायत श्री दिनेश नाग की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई है।

कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत ने समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने टीएल के लंबित प्रकरणों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि किसानों को खाद और यूरिया के लिए किसी

0 स्कूल और आंगनबाड़ी में गैस से खाना पकाने और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश

0 युक्ति युक्तकरण अंतर्गत जॉइनिंग नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही के लिए निर्देश

0 डीएमएफअंतर्गत स्वीकृत कार्यों को आगामी दस दिवस में प्रारंभ करने के कलेक्टर ने दिये निर्देश

0 पीएम आवास पैपल लगाकर हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश

0 समय सीमा की बैठक में हुई विभागीय कामकाज की समीक्षा

कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत ने समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने टीएल के लंबित प्रकरणों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि किसानों को खाद और यूरिया के लिए किसी

विश्व के सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री की पहचान बनाकर नरेन्द्र मोदी ने देश को किया गौरान्वित

0 नगर पालिक निगम कोरबा के शारदा विहार एवं कोहड़िया उद्यान के ” नमो पार्क ” नामकरण पट्टिका का अनावरण किया उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने

कोरबा संवाददाता ।
प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व के सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री की पहचान कायम कर हमारे भारत देश को गौरान्वित किया है। अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को विकास की नई ऊंचाईयों में पहुंचाया, तो वहीं दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कराकर समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। उन्होंने कहा कि मुझे अत्यंत खुशी है कि आज इन दोनों उद्यानों के ” नमो पार्क ” नामकरण की पट्टिका का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
उक्त बातें उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने नगर पालिक निगम कोरबा के शारदा विहार एवं कोहड़िया उद्यान में ” नमो पार्क ” नामकरण पट्टिका के अनावरण कार्यक्रम के



दौरान कही। यहाँ उल्लेखनीय है कि महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत की पहल पर नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत अन्य उद्यानों के साथ शारदा विहार मुड़ाई तालाब के समीप स्थित उद्यान एवं कोहड़िया मेन रोड स्थित उद्यान का नामकरण ” नमो पार्क ” के नाम पर किया गया है। आज इन दोनों उद्यानों में आयोजित गरिमापूर्ण कार्यक्रमों के दौरान प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने ” नमो पार्क ” नामकरण पट्टिका का अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर

श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने की, वहीं आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय, सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री गोपाल मोदी, वरिष्ठ पार्षद नरेन्द्र देवांगन, अशोक चावलानी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इस मौके पर उद्यानों के ” नमो पार्क ” नामकरण की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने आगे कहा कि आज हम सब गौरान्वित है कि हमारे देश को श्री नरेन्द्र मोदी जैसे महान व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री प्राप्त हुए हैं, उन्होंने कहा कि 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री श्री मोदी का जन्मदिन था, उनके जन्मदिन 17 सितम्बर से महात्मा गांधी जी व पं.लालबहादुर

जीएसटी बचत उत्सव : मंत्री लखनलाल देवांगन सहित जनप्रतिनियों ने किया व्यापारियों और उपभोक्ताओं से आत्मीय संवाद

कोरबा संवाददाता। शक्ति और समृद्धि के पर्व शारदीय नवरात्र से जहां त्योहारों का आगाज होता है, कारोबार के लिए भी पीक सीजन का शुभारंभ माना जाता है। ऐसे में इस वर्ष ठैजू रिफॉर्म के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए नमो उपहार की धूम दिखाई दे रही है। इस विषय पर व्यापारियों एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य हुए संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे श्रम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से जहां बाजार में रैनक की आमद से व्यवसाई बंधुओं के चेहरे खिल उठे हैं,



जीएसटी में छूट की राहत ने आम लोगों के लिए भी खरीदी आसान बनाकर त्योहारों की खुशी को दोहरा कर दिया है। बाजार, कारोबार और त्योहारों सीजन के लिए संजीवनी की तरह नवाजे गए मोदी सरकार के इस तोहफे से हर्षित स्थानीय व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया

जीएसटी दरों की जानकारी साझा करने के अलावा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और खरीदारी पर भी जोर दिया गया। ‘नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों’ पर संवाद में व्यापारियों और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने और उपभोक्ताओं को नई जीएसटी दरों की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नई जीएसटी दरों के लागू होने से वस्तुओं की कीमतों में आई कमी का सीधा लाभ आमजन तक पहुँच रहा है। बाजार में उत्साह का वातावरण है और विक्रेता व उपभोक्ता प्रधानमंत्री श्री /दंतमदकतंउवकप जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, मंडल अध्यक्ष मनोज लहरे, पार्षद नरेंद्र देवांगन, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, नवीन अरोरा, तुलसी ठाकुर, नारायण ठाकुर, ईश्वर साहू, शैलेन्द्र यादव, अंजय अग्रवाल सहित अधिक संख्या में भाजपा के पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

एचटीपीएस चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आज एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा कल

कोरबा। हसदेव ताप विद्युत गृह (एचटीपीएस) कोरबा पश्चिम के विभागीय चिकित्सालय में सेवा पखवाड़ा के तहत 24 सितंबर को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। इसके दूसरे दिन 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। शासकीय कार्यक्रम के अनुसार यहां सेवा पखवाड़ा का आयोजन 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक किया जा रहा है। गुरुवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मस्तिष्क एवं नस रोग विशेषज्ञ (न्यूरो सर्जन)डॉ. प्रदीप त्रिपाठी (एमबीबीएस., एमएस. एमसीएच. न्यूरो) एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक सर्जन) डॉ. श्रीयस गूमस्कर (एमबीबीएस. डीएनबी. आर्थोपेडिक्स) चिकित्सा परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। मुख्य अभियंता श्री पीके श्रीवास्तव शिविर का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करने एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेने का आह्वान किया है। विभागीय चिकित्सालय के अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित समस्याओं की जांच व परामर्श, गर्दन, कमर, शेड़ की हड्डी, नस दर्द, सायटिका व झुनझुनी की जांच, सिरदर्द (माइग्रेन), चक्कर आना, नींद की समस्या का परामर्श, एक्सरीडेंट व चोट से संबंधित समस्याओं की जांच, बच्चों के जन्मजात हड्डी रोग, नस संबंधी रोगों का परामर्श के साथ ही अन्य आर्थोपेडिक व न्यूरो रोगों का निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा।

महतारी सदन के माध्यम से महिलाओं को मिलेगा रोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसर-मंत्री श्री लखन लाल देवांगन

मुख्यमंत्री ने कनबेरी और बोईदा के महतारी सदन का किया चर्चुअली लोकार्पण

कोरबा संवाददाता। महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से एक दूरदर्शी पहल की शुरुआत की गई, जो उन्हें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में भी नई पहचान दिलाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा ने धमतरी जिले से प्रदेश के 17 जिलों में 51 महतारी सदन का एक साथ शुभारंभ किया। प्रदेशव्यापी लोकार्पण कार्यक्रम के अंतर्गत कोरबा जिले के ग्राम पंचायत कनबेरी और ग्राम पंचायत बोईदा में भी नवनिर्मित महतारी सदन का लोकार्पण किया गया।



गया। प्राथमिक शाला कनबेरी परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में वाणिज्य, उद्योग, श्रम एवं आबकारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने फीता काटकर और विधिविधानपूर्वक पूजा अर्चना कर भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने इसके लिए माताओं-बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। अपने संबोधन में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव

साय के नेतृत्व में माताओं और बहनों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार सार्थक कार्य किए जा रहे हैं। इन महतारी सदनों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही उन्होंने इसके लिए माताओं-बहनों को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ

संचालित कर रही हैं। सुकन्या योजना, लखपति दीदी योजना, हर घर जल और हर घर शौचालय योजना जैसी योजनाओं ने सुरक्षा का मजबूत आधार दिया है। हमारी सरकार ने अल्प समय में ही मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना, तैदृपत्ता का बढ़ा हुआ दाम, महतारी वंदन योजना, श्री राम लला दर्शन योजना जैसे वायदों को पूरा कर दिखाया है साथ ही हमारी सरकार विकास पर विश्वास रखती है। मंत्री श्री देवांगन ने नवरात्रि के प्रथम दिवस से प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा किए गए जीएसटी सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि यह निर्णय आम जनता के लिए लाभकारी साबित होगा। अब आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री

राधासागर तालाब कटघोरा मे बाढ़ बचाव और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कोहड़िया में गैस लिकेज मॉक ड्रिल का आयोजन 25 को

कोरबा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार जिला आपदा प्रबंधन के संयुक्त तत्वाधान में जिला प्रशासन द्वारा 25 सितंबर गुरुवार को प्रातः 10 बजे राधासागर तालाब कटघोरा में बाढ़ बचाव के संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसी तरह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कोहड़िया कोरबा में दोपहर 01 बजे गैस लिकेज के संबंध में मॉक ड्रिल आयोजित किया जायेगा। अपर कलेक्टर ने बताया कि यह मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने तथा आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। यह केवल एक प्रशिक्षण प्रक्रिया है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागरिकों से अपील की गई है कि अभ्यास के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा लोगों को सही जानकारी प्रदान करें और मॉक ड्रिल में प्रभासन का पूरा सहयोग करें।

जिला स्तरीय चयन समिति गठित

कोरबा)। कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा संचालनालय महिला एवं बाल विकास रायपुर के निर्देशानुसार वीरगंगा रानी अवंतैबाई लोधी स्मृति पुरस्कार, मिनीमाता सम्मान (महिला उत्थान) और माता बहादुर कलारिण सम्मान वर्ष 2025 हेतु प्राप्त नामांकन में से सर्वोत्कृष्ट एक महिला का नाम चयन कर अनुपंसा सहित संचालनालय को भेजे जाने हेतु 05 सदस्यीय ।

एसीआई में 60 वर्षीय मरीज को मिला जीवन,100 प्रतिशत ब्लॉकेज पर पाई जीत

रायपुर। पं. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) अब न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्यों के मरीजों के लिए भी जीवनदाता बनता जा रहा है। हाल ही में एसीआई के कार्डियोलॉजी विभाग में मध्यप्रदेश निवासी 60 वर्षीय मरीज के हृदय की 100% ब्लॉक हो चुकी चार नसों की सफल एंजियोप्लास्टी की गई। मरीज के परिजनों के अनुसार, मरीज लंबे समय से दवाओं के सहारे जीवन जी रहे थे। मध्यप्रदेश के कई बड़े अस्पतालों ने एंजियोप्लास्टी करने से मना कर दिया था। इस बीच उनके एक करीबी रिश्तेदार से पता चला कि एसीआई में कुछ वर्ष पूर्व एक मरीज के जटिल हृदय रोग का सफल उपचार किया गया है। कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुई इस प्रक्रिया में राइट फीमोरल एंजियोप्लास्टी के जरिए मरीज की ब्लॉक नसों को खोला गया। फिलहाल मरीज पूरी तरह स्वस्थ हैं और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पड़ोसी राज्यों से पहुंच रहे मरीज एसीआई पर भरोसा जताते हुए दूसरे राज्यों से मरीज रायपुर पहुंच रहे हैं। स्वयं मरीज अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि जब कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने कह दिया था कि उनके यहाँ इलाज संभव नहीं है तो एसीआई बड़ी उम्मीद लेकर आया था। डॉक्टर से हमने कह भी दिया था कि जितना भी रिस्क हो, आप इलाज की तैयारी कीजिये, मैं उसके लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हूँ। अंततः यहाँ के डॉक्टरों ने मुझे नया जीवनदान दिया। सामान्य एंजियोप्लास्टी से मिली सफलता डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि पाँच वर्ष पूर्व भी मध्यप्रदेश से आए एक मरीज की सफल लेजर एंजियोप्लास्टी की गई थी।

मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे मार्ट,ग्राहकों से की मुलाकात,ग्राहक बोले जीएसटी रिफॉर्म्स, बचत क्रांति

जब मुख्यमंत्री खुद बने ग्राहक : घरेलू सामान की शॉपिंग कर उठाया जीएसटी दरों में कटौती का लाभ

जीएसटी बचत उत्सव को लेकर जनभावनाओं से रूबरू होने के मार्ट पहुंचे मुख्यमंत्री

रायपुर। जब मुख्यमंत्री खुद बने ग्राहक : घरेलू सामान की शॉपिंग कर उठाया जीएसटी दरों में कटौती का लाभजब मुख्यमंत्री खुद बने ग्राहक : घरेलू सामान की शॉपिंग कर उठाया जीएसटी दरों में कटौती का लाभ - राजधानी रायपुर के सरोना स्थित शुभम ंके मार्ट- में रोजमर्रा की ज़रूरत का सामान खरीद रहे लोग उस समय सुखद आश्चर्य से भर उठे, जब उन्होंने देखा कि जीएसटी बचत का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं उसे देखने स्वयं प्रदेश के मुखिया आए हैं। दरअसल, आज जीएसटी बचत उत्सव को लेकर जनभावनाओं से रूबरू होने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ंशुभम के मार्ट- पहुंचे। उन्होंने खुद ग्राहक बनकर 1,645 रुपये के घरेलू सामान की शॉपिंग की एवं यूपीआई से भुगतान भी किया।इस दौरान उन्होंने खरीदारी कर रहे लोगों से बातचीत की और जीएसटी दरों में कटौती से घरेलू



सामानों के मूल्य में आए फर्क के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मार्ट पहुंचकर ज़रूरत के सामान खरीदे और जीएसटी दरों में कमी का लाभ लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आत्मीयता से लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने खरीदारी कर रही गृहिणियों से घरेलू बजट पर आए असर की जानकारी ली, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों से उनकी दिनचर्या के बारे में पूछताछ की। इस बीच उन्होंने रोजमर्रा का सामना खरीदते हुए अन्य ग्राहकों से

आत्मीयतापूर्वक वार्तालाप किया। मुख्यमंत्री का यह आत्मीय व्यवहार देखकर मौजूद लोग गदगद हो उठे और कहा कि प्रदेश का मुखिया आज हमारे बीच एक आम आदमी की तरह शामिल है। इस दौरान उन्होंने खरीददारों से चर्चा करते हुए जीएसटी सुधारों पर लोगों के विचार सुने। लोगों ने बताया कि दवाइयों और राशन की कीमत घटने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए बोले--यही तो असली मकसद है कि सुधार की गूंज आम जनता तक पहुंचे।- इसके बाद उन्होंने खुद भी सामान

खरीदा और नई कीमतें देखकर कहा--यह सुधार केवल कागज पर नहीं, बल्कि हर परिवार की ज़िंदगी में दिखाई देने वाला परिवर्तन है।मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को स्वदेशी की मुहिम का साथ देने का आग्रह भी किया, जिस पर लोगों ने कहा आप आगे बढ़े ,हम आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए खरीदारी कर रहे रिटायर्ड एयरफ़र्स अधिकारी श्री टी. पी. सिंह ने कहा कि आने वाले समय में जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए जीएसटी सुधार को ऐतिहासिक बजट क्रांति के रूप में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा--पहले हम जितने पैसों में 30 दिन का राशन लेते थे, अब उन्हीं पैसों से 40 दिन से अधिक का राशन ले पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ही इतना बड़ा साहसिक निर्णय ले सकते थे, कोई और ऐसा नहीं कर पाता।राजधानी रायपुर के अवती विहार निवासी श्री लक्ष्मण नैनवानी ने बताया कि जीएसटी सुधार का सकारात्मक प्रभाव शिक्षा से भी जुड़ा है। शुभम ंके मार्ट- में मुख्यमंत्री को नोटबुक दिखाते हुए उन्होंने कहा--पहले इस पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे शून्य कर दिया है। इस ऐतिहासिक कदम

से कॉपियाँ और आवश्यक स्टेशनरी सस्ती हो गई हैं। ऐसा निर्णय हमारे प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया--पहले मैं बच्चों के लिए सालाना लगभग 2,000 रुपये की स्टेशनरी लेता था और अब इसमें लगभग 240 रुपये की बचत हो रही है। चार जरूरी सामान खरीदने आए, जीएसटी छूट से खरीदा 4 गुना अधिक सामान मार्ट में खरीदारी करने पहुंचे श्री मुखलीधर ने मुख्यमंत्री से बातचीत में बताया--मैं आज केवल 4 जरूरी सामान खरीदने आया था, लेकिन जीएसटी दरों में कमी देखकर 4 गुना अधिक सामान खरीद लिया। जीएसटी में व्यापक सुधार से रोजमर्रा की सामग्रियाँ सस्ती हुई हैं और हमें सीधा लाभ मिल रहा है। शुभम ंके मार्ट- में खरीदारी करने पहुंचे चंगोराभाटा निवासी दंपति श्री जितेंद्र और श्रीमती पद्मा देवानग ने कहा--हमारे मासिक बजट में 10 प्रतिशत की कमी आई है।- गृहिणी श्रीमती पद्मा ने नए प्राइस टैग देखकर कहा--पहले यही डिटर्जेंट और मसाले में ज्यादा कीमत में खरीदती थी। अब दरों में कटौती के बाद कम दाम देखकर सचमुच खुशी हो रही है। ल्योहारी खरीदारी में काफी बचत हो रही है।

ट्रिपल-आईटी नवा रायपुर में डिजिटल उत्पादकता संवर्धन एवं एआई एकीकरण विषय पर प्रशिक्षण का शुभारंभ



रायपुर। नवा रायपुर स्थित ट्रिपल-आईटी में आज डिजिटल उत्पादकता संवर्धन एवं एआई एकीकरण विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसे राज्य सरकार की ओर से मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को आई.टी एवं ए.आई के नवीनतम तकनीकों और अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित करने, प्रशासनिक कामकाज की गति बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, विशिष्ट अतिथि सुशासन एवं अभिसरण विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत एवं अध्यक्षता ट्रिपल-आईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. ओपी व्यास ने की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागी अधिकारियों-कर्मचारियों को जिम्मेदार प्रशासन को मजबूत करने के लिए डिजिटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की गई। पहले दिन प्रतिभागियों को MS Word, Google Docs, E&cel ंड00U Google Sheets के उन्नत फीचर्स के साथ-ट्रु के उपयोग और डेटा मॉडलिंग की ट्रेनिंग दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि कौशल उन्नयन सतत प्रक्रिया है, इससे व्यक्ति और कार्यसंस्कृति दोनों ही निखरते हैं, उन्होंने एआई-आधारित प्रशिक्षण को कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि में मील का पत्थर बताया और प्रतिभागियों से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया।

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने नागरिक केंद्रित शासन में तकनीक की अहम भूमिका पर अपने विचार रखते हुए सरकारी कार्यकुशलता बढ़ाने में एआई टूल्स की भूमिका पर जोर दिया। श्री भगत ने ई-ऑप्स प्रणाली का उदाहरण देते हुए कहा कि तकनीक का प्रभावी उपयोग शासन को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बना सकता है।

ट्रिपल-आईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. ओपी व्यास ने कार्यशाला में अपना सम्बोधन देते हुए कहा कि एआई के स्मार्ट उपयोग के लिए हमें जागरूक और सतर्क रहना होगा। एआई के व्यवहारिक अनुप्रयोग से शुरुआत कर उसके बारे में निरंतर सीखने की आदत हमें एआई से और अधिक फ़ैदली बनाएगी। हमें डेटा को सुरक्षित रखते हुए एआई का उपयोग करना होगा, जिसके लिए हमें एआई को संवेदनशील जानकारी देने से बचना होगा ताकि पब्लिक डोमेन में जाकर इनका दुरुपयोग न हो सके।

वहीं, प्रो. के. जी. श्रीनिवास ने भरोसा दिलाया कि यह प्रशिक्षण उच्च गुणवत्ता वाला और परिणामोन्मुखी होगा। इस प्रशिक्षण के प्रथम चरण में सामान्य प्रशासन, गृह एवं अन्य विभागों के 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए, जो कि 24 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर 2025 तक चलेगा।

सुराना महाविद्यालय में ‘अंजोर मिशन 2047’ पर एक दिवसीय सेमिनार का भव्य आयोजन

दुर्गा। सुराना महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवसीय सेमिनार ‘अंजोर मिशन 2047’ का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षण समिति दुर्ग के अध्यक्ष प्रवीण चंद्र तिवारी तथा मुख्य वक्ता के रूप में सीएसपीडीसीएल के मुख्य अभियंता संजय खंडेवाला उपस्थित रहे।

सेमिनार में महाविद्यालय के प्राचार्य, अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा, पावर प्लॉट्स की कार्यप्रणाली, सोलर एनर्जी की उपयोगिता और केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सस्मिडी की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही राज्य सरकार की ऊर्जा संबंधी विभिन्न योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया।

मुख्य वक्ता संजय खंडेवाला ने छात्राओं को ऊर्जा क्षेत्र में करियर संभावनाओं एवं तकनीकी पहलुओं से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सस्टेनेबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी मिशन का कितना अधिक महत्व होगा। कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

नवरात्रि के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने माँ कंकालीन मईया का दर्शन कर आशीर्वाद लिया



रायपुर /बालोद। नवरात्रि के पावन अवसर पर बालोद जिले में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव बालोद प्रवास के दौरान नवरात्रि के दूसरे दिन ग्राम पेटेचुआ स्थित माँ कंकालीन मईया के दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगाकर माता रानी से प्रार्थना किए। मंत्री गजेंद्र यादव ने मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं का आशीर्वाद लिया और भक्तों के साथ हर्षोल्लास में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पर्व हमारे समाज में अध्यात्म और सांस्कृतिक मूल्यों को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है

और इस अवसर पर सभी को मिलकर माँ की भक्ति में लीन होना चाहिए।इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख, जिला महामंत्री राकेश यादव, जिला मुख्य आयुक्त राकेश यादव और मंदिर समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। समारोह में क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और भक्तिभाव के साथ आयोजन को सफल बनाया। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। श्रद्धालुओं के लिए पानी, पुरुखा और बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति ने मिलकर भक्तों

के लिए सुचारु और शांतिपूर्ण दर्शन सुनिश्चित किए। भक्तों ने कहा कि मंत्री गजेंद्र यादव के साथ दर्शन का अवसर मिलना उनके लिए गौरव और आशीर्वाद का समय था।

उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ दीप जलाए और माता की आराधना की। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन दिया और आयोजन के संचालन में सहयोग किया। कैबिनेट मंत्री ने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि नवरात्रि केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव और एकता का संदेश भी देती है। यह आयोजन बालोद में नवरात्रि के उत्सव को और भव्य बनाता है और स्थानीय समाज में उत्साह और एकजुटता का संदेश फैलाता है। मंत्री गजेंद्र यादव की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा और भक्तिभाव को और बढ़ा दिया।

समारोह के अंत में सभी उपस्थित लोग माँ कंकालीन मईया के चरणों में आशीर्वाद लेने के बाद प्रसन्नचित होकर लौटे। मंदिर समिति ने भी भविष्य में ऐसे धार्मिक आयोजनों को और भव्य और सुव्यवस्थित बनाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार बालोद में नवरात्रि के दूसरे दिन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मंत्री, भाजपा पदाधिकारी और स्थानीय समाज के लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल हुए।

अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र से ग्रामीणों को मिल रही बैंकिंग व अन्य सेवाओं का लाभ : मंत्री

गुजरात के हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन ने दी हार्ट एवं लंग ट्रांसप्लांट की जानकारी

रायपुर । छत्तीसगढ़ कार्डियक सर्जन और कार्डियक एनीस्थिस्टिस्ट एसोसिएशन के द्वारा के द्वारा छत्तीसगढ़ में हार्ट ट्रांसप्लांट प्रारंभ करने के लिए को राजधानी रायपुर के एक होटल में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में गुजरात के अहमदाबाद से सिम्स हॉस्पिटल के जाने-शहाह उपस्थित रहे। डॉ धीरेन शाह अभी तक 60 से अधिक हार्ट एवं हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट कर चुके हैं।

वे गुजरात में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के पॉयनियर भी हैं। छत्तीसगढ़ के हार्ट सर्जन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर कुष्णांत साहू एवं सेक्रेटरी डॉ अरुण अंडप्पन ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी प्राप्रंभ करना अति आवश्यक है क्योंकि यहां पर ऐसे मरीज आते हैं जिनकी हार्ट की पॉपिंग 15 या 20त होती है जिसको सामान्य भाषा में हार्ट फेल्योर कहा जाता है की संख्या बहुत अधिक है। यदि ऐसे में किसी ज़रूरतमंद को किसी दुर्घटनाग्रस्त ब्रेन डेड मरीज का

हृदय मिल जाए तो ज़रूरतमंद मरीज की जिंदगी संवर जाती है। इस सेमिनार में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के अतिरिक्त हृदय के माईट्रल वॉल्व और ट्राईकस्पिड वॉल्व के सर्जरी के नए नए तकनीक के बारे में भी चर्चा की गई। इसमें यह बताया गया कि माईट्रल वॉल्व में लीकेज के हर मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती बल्कि कुछ मरीज दवाइयां से भी ठीक हो सकते हैं। इस सेमिनार में प्रदेश भर से 35 से अधिक कार्डियक सर्जन , कार्डियक एनीस्थिस्टिस्ट एवं कार्डियक सर्जरी के अध्ययनरत स्टूडेंट सम्मिलित हुए। लोगों में जागरूकता पर जोर डॉ केके साहू के मुताबिक छत्तीसगढ़ में डोनर हार्ट की अत्यंत कमी है , जिसका एक ही कारण है कि लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता की कमी है। सरकार एवं समाज सेवा संस्था द्वारा लोगों को अंगदान के विषय में समझाया जा रहा है और लोग धीरे-धीरे जागरूक भी हो रहे हैं। डॉ धीरेन शाह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। संस्था के साथ-साथ हार्ट सर्जन एवं कार्डियक एनेस्थेटिक को इसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है।

जनजागरूकता कार्यक्रमों में छात्रों और अधिकारियों ने ली नशामुक्ति की शपथ

रायपुर । सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत कलेक्टर के मार्गदर्शन में 17 से 22 सितम्बर 2025 तक रायपुर जिले में नशामुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में रैलियां, गीत-संगीत, भाषण, शपथ ग्रहण और नुकड़ नाटक शामिल रहे। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों, अधिकारियों और आम नागरिकों को नशे के दुष्परिणाम और नशामुक्त जीवन के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इसी कड़ी में 17 सितम्बर को शासकीय दुष्टिहीन एवं श्रवण बाधित विद्यालय, मठपुरेना रायपुर में लगभग 350 प्रतिभागी ने भाग लिया। इसी प्रकार 18 सितम्बर को शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय, माना कैप रायपुर में लगभग 225 प्रतिभागी, 19 सितम्बर को नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाड, हीरापुर रायपुर में लगभग 250 प्रतिभागी, 20 सितम्बर को माधव राव सप्रे शाला रायपुर एवं उत्कृष्ट स्वामी आत्मानंद स्कूल, बूढ़ातालाब में लगभग 260 प्रतिभागी, 21 सितम्बर को शासकीय नवीन वृद्धाश्रम एवं शासकीय बालगृह, माना कैप रायपुर में लगभग 180 प्रतिभागी एवं 22 सितम्बर को दुर्ग महाविद्यालय एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर में हुए कार्यक्रमों में लगभग 280 प्रतिभागियों ने भाग लिया 7 कुल 1545 छात्र-छात्राएं, अधिकारी एवं कर्मचारी इस अभियान का हिस्सा बने। इन कार्यक्रमों के दौरान नशामुक्ति रैलियों और नुकड़ नाटकों के जरिए यह संदेश दिया गया कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज को गम्भीर रूप से प्रभावित करता है। नशे से छुटकारा पाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति केंद्रों की सुविधाओं, परामर्श सेवाओं, दवाइयों और मनोवैज्ञानिक सहायता की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि नशा त्यागने से न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा आती है।